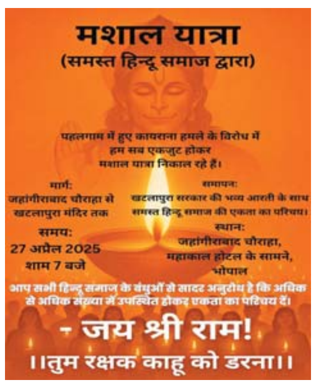

दैनिक
सांध्य प्रकाश
भोपाल की धड़कन

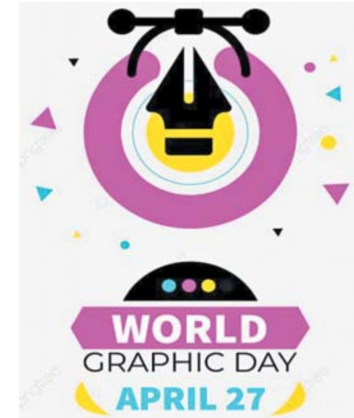

वर्ष 54/ अंक 260/ पृष्ठ 8 / मूल्य ₹ 2.10 संस्थापक- स्व. सुरेंद्र पटेल ▪आर.एन.आई 22296/71 ▪डाक पंजीयन मप्र/भोपाल/125/12-14

भोपाल, रविवार 27 अप्रैल 2025 भोपाल से प्रकाशित dainiksandhyaprakash.in

सांध्यप्रकाश विशेष

आज फिर कुपवाड़ा में आतंकी हमला, स्थानीय निवासी की मौत

जम्मू। एक बार फिर रविवार को आतंकियों ने कुपवाड़ा के कंडी में हमला किया है। इस बार आतंकियों ने स्थानीय निवासी को निशाना बनाते हुए गोलीबारी की। जिसमें एक शख्स घायल हो गया, उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। इसके पहले 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 28 लोग मारे गए थे। कुपवाड़ा के कंडी खास निवासी गुल रसूल माग्रे पर आतंकियों ने गोलीबारी की है, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने बताया कि उनके पेट में गोली लगी थी। इधर, पहलगाम हमले के बाद से पूरी कश्मीर घाटी में 63 आतंकी ठिकानों पर छापे मारे गए और 1,500 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। अकेले अनंतनाग से ही करीब 175 संदिग्ध पकड़े हैं।

पहलगाम हमले में भारत को मिला यूएई का साथ, राष्ट्रपति नाहयान ने कहा, हम भारत के साथ

अबू धाबी/नई दिल्ली। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने पहलगाम हमले की आलोचना करते हुए आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देने की बात कही है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। उन्होंने प्रधानमंत्री से बात करते हुए पहलगाम हमले की कड़ी आलोचना की। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति नाहयान के बीच हुई बातचीत की जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बातचीत के दौरान दोनों नेता इस बात एकमत थे कि आतंकवाद को उसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद की ओर से व्यक्त की गई संवेदनाओं के लिए उनका आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति नाहयान से बात करते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है और हमले के अपराधियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति नाहयान की इस बातचीत से पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। यूएई का नाम दुनिया के बड़े मुस्लिम देशों में आता है और पाकिस्तान अक्सर दुनिया के सामने उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त बताता रहा है। ऐसे में यूएई का भारत का पक्ष लेना पाकिस्तान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। क्योंकि, दुनियाभर के नेता पहले पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान की निंदा कर चुके हैं।

पहलगाम हमले के बाद संघ की 'छोटी टोली' की बैठक आज, भागवत भी होंगे शामिल

नई दिल्ली। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पहली बार आरएसएस के सभी बड़े अधिकारियों की बैठक आज दिल्ली में हो रही है, माना जा रहा है कि बैठक में इस घटना को लेकर भी गहन चर्चा की जाएगी। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से इसके गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में भी हमले को लेकर खासी नाराजगी देखी जा रही है। संघ की रविवार को आरएसएस के अधिकारियों के कोर ग्रुप (छोटी टोली) की बैठक दिल्ली स्थित संघ के झंडेवालान ऑफिस में बुलाई गई है। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत के अलावा सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और सभी 6 सह सरकार्यवाह मौजूद होंगे। संघ का शीर्ष नेतृत्व जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर बैठक के दौरान चर्चा कर सकता है। माना जा रहा है कि इस बैठक में संघ शताब्दी वर्ष पर चल रहे कामों की प्रगति रिपोर्ट और समीक्षा पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में संघ से जुड़े संगठनों की ओर से किए जा रहे कामों को लेकर भी चर्चा और समीक्षा होती है। आरएसएस के सभी शीर्ष अधिकारियों का अगले 3 दिन तक दिल्ली में जमावड़ा रहेगा। छोटी टोली की बैठक हर एक से डेढ़ महीने के अंतराल पर होती है।

मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा

पहलगाम हमले के दोषियों को बख्शेंगे नहीं

हमले के बाद देश का खून खौल रहा है, पीड़ितों को न्याय मिलकर रहेगा

नई दिल्ली। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एक बार फिर से पहलगाम हमले को लेकर दुख जताया और साथ ही पहलगाम के दोषियों को कड़ी सजा देने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि पहलगाम की घटना ने देशवासियों को पीड़ा पहुंचाई है और इसे लेकर देशवासियों के मन में गहरी पीड़ा है। लोग पीड़ित परिजनों के दर्द को महसूस कर सकते हैं। हर भारतीय का खून आतंक की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी और लोकतंत्र मजबूत हो रहा था। पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हो रही थी और लोगों की कमाई बढ़ रही थी, लेकिन देश के दुश्मनों को और जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी चाहते हैं कि कश्मीर फिर से तबाह हो जाए। इस मुश्किल वक्त में 140 करोड़ देशवासियों की एकता सबसे बड़ा आधार है।

भारत के लोगों में जो आक्रोश है, वो पूरी दुनिया में है

पीएम मोदी ने कहा कि हमें इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक दृढ़ राष्ट्र के रूप में अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत करना है। भारत के लोगों में जो आक्रोश है, वो पूरी दुनिया में हैं। इस आतंकी हमले के बाद दुनियाभर से लगातार संवेदनाएं आ रही हैं। कई राष्ट्राध्यक्षों ने उन्हें भी फोन करके पहलगाम की घटना पर दुख जताया है। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सभी ने कठोर निंदा की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देश के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को भरोसा देता हूं उन्हें न्याय मिलेगा और न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा।

देशवासियों से सतत् संवाद के अभूतपूर्व माध्यम मन की बात के 121वें संस्करण को सुनते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने भोपाल के वार्ड क्रमांक 50 के जी-3 गुलमोहर सील पब्लिक स्कूल के सामने पार्क स्थित बूथ क्रमांक 200 पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात को सुना।

देशवासियों से सतत् संवाद के अभूतपूर्व माध्यम मन की बात के 121वें संस्करण को सुनते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव।

मप्र राजपत्रित अधिकारी संघ का प्रांतीय सम्मेलन में सीएम डॉ. यादव ने कहा

प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों को मिलेगा भारत सरकार के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह घोषणा मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ भोपाल के नार्मदीय भवन में आयोजित प्रांतीय सम्मेलन में की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों को 1-7- 2024 से 3त्न और 1-1-2025 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त स्वीकृत करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों को भारत सरकार के कर्मचारियों के समान ही 55% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि के फल स्वरुप एरियर राशि का भुगतान पांच समान किस्तों में जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक दीवाली अच्छी मनाकर किया जाएगा।

द आम्बेडकर यूथ कॉन्क्लेव की संगोष्ठी के समापन सत्र को सीएम डॉ मोहन यादव ने संबोधित किया।इस मोके पर प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, विधायक भगवान दास सबनानी भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री करेंगे 'एमपी टेक ग्रोथ' कॉन्क्लेव-2025' का शुभारंभ

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मध्यप्रदेश को टेक्नोलॉजी और डिजिटल नवाचार का केन्द्र बनाने के उद्देश्य से आयोजित 'एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव-2025' का शुभारंभ इंदौर के 'ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर' में करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कॉन्क्लेव देश-दुनिया के टेक दिग्गजों के लिए निवेश का स्वर्णिम अवसर सिद्ध होगा। राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का यह आयोजन जीआईएस-भोपाल में आए निवेश प्रस्तावों को मूर्त रूप देने का महत्वपूर्ण प्रयास है। 'एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव' प्रदेश का पहला पूर्णतः सेक्टर आधारित टेक-कॉन्क्लेव होगा, जो फरवरी में भोपाल में आयोजित जीआईएस में प्राप्त निवेश प्रस्तावों को धरातल पर साकार करने का मंच बनेगा। कार्यक्रम में Google, Microsoft, NVIDIA जैसी बिग-टेक कंपनियों सहित 300 से अधिक तकनीकी विशेषज्ञ, उद्योगपति, नीति-निर्माता और निवेशक शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास भोपाल से उज्जैन में सत्यज फाउंडेशन द्वारा आयोजित महिला केंद्रित रोजगार पर्व में शामिल लोगों को वर्चुअली संबोधित किया

वैष्णो देवी यात्रियों में गिरावट, यात्री संख्या 40 से घटकर 20 हजार के नीचे पहुंची

कटड़ा। पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद मां वैष्णो देवी के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। सामान्य दिन में देशभर से भारी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आते थे, लेकिन सुरक्षा को लेकर फैली आशंकाओं के चलते बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं का आगमन कम हो गया है। शनिवार को शाम छह बजे तक 18 हजार 600 श्रद्धालु भवन की ओर प्रस्थान कर चुके थे। जबकि इन दिनों 40 हजार श्रद्धालु हर दिन धर्मनगरी पहुंचते थे। कटड़ा में होटल संचालकों, ट्रैवल एजेंट्स और स्थानीय दुकानदारों के अनुसार पिछले कुछ दिन में यात्रा बुकिंग में 30-40 प्रतिशत तक की गिरावट देखी गई है।

कराची में धारा 144 लागू, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बड़ी बैठकों का दौर जारी

इस्लामाबाद/कराची। पहलगाम में आतंकी हमले के 5 दिन बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान को किसी बड़े हमले का डर सता रहा है। भारत के सख्त रूख से डरे पाकिस्तान ने अपने सबसे बड़े शहर कराची में धारा-144 लागू कर दिया है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में बड़ी-बड़ी बैठकों का दौर जारी है। अकेले पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार हर दिन 2-3 बैठक कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर की भी अलग-अलग बैठकें हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कराची के पुलिस कमिश्नर ने शहर में 144 लागू कर दिया है। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि अगले 3 महीने के लिए इसे लागू किया गया है। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि कराची में लोग घरों से बाहर कम निकलें।

पाकिस्तान में आपातकाल, पीओके में बाढ़ जैसी स्थिति, झेलम नदी में अचानक जल स्तर बढ़ने से मची अफरा-तफरी

जम्मू। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में शनिवार दोपहर झेलम नदी का जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ गया, जिससे कई क्षेत्रों में पानी भर गया और हालात बाढ़ जैसे बन गए। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने फौरन अलर्ट जारी कर दिया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की सलाह दी गई।

जानकारी के अनुसार, हट्टियन बाला ज़िले में जल संकट को देखते हुए 'वाटर इमरजेंसी' लागू कर दी गई है। साथ ही मस्जिदों से भी लगातार लाउडस्पीकर के माध्यम से चेतावनियाँ दी जा रही हैं ताकि लोग सतर्क रहें। मुजफ्फराबाद के डिप्टी कमिश्नर मुदस्सर फारूक ने जनता से अपील की है कि वे झेलम नदी के आस-पास जाने से बचें। उनका आरोप है कि भारत ने जानबूझकर झेलम में अतिरिक्त पानी छोड़ा है, जिससे यह आपदा उत्पन्न हुई है। स्थानीय अधिकारियों ने लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को सतर्क किया और उन्हें नदी के किनारे बसे अपने घरों को छोड़ने की सलाह दी। मुजफ्फराबाद और चकोटी जैसे शहरों में लोग जलस्तर के अचानक बढ़ने से चिंतित हो गए।

कश्मीर में होटलें खाली, सड़कें सुनी, वादियों में पसरा डर व सन्नाटा, टूरिज्म इंडस्ट्री फिर तबाह

नई दिल्ली। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। शांत टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहलगाम में बीते मंगलवार को आतंकवादियों ने 28 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। मारे गए लोगों में ज्यादातर पर्यटक थे, जो परिवार के साथ यहां छुट्टियां मनाने आए थे। यह हमला ऐसे समय हुआ, जब घाटी में हालात सामान्य थे और टूरिज्म इंडस्ट्री एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुकी थी। यहां के होटल फुल थे, डल लेक पर शिकारे गुलजार थे, टैक्सियां लाइन में खड़ी थीं और एयरपोर्ट से लेकर पहलगाम तक हर जगह पर्यटकों की चहल-पहल दिखाई दे रही थी, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर कश्मीर की वादियों में डर और सन्नाटा फैलाने का काम कर दिया। कुछ सालों में जम्मू-कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर में बड़ा उछाल देखा जा रहा था। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में अस्थिरता का माहौल था, फिर कोविड ने तो सब कुछ रोक दिया। लेकिन 2021 से हालात सुधरने शुरू हो गए थे। केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार ने हमले की निंदा करते हुए कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुरक्षा बढ़ा दी गई और हालात को संभालने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन, लोगों के अंदर जो खौफ है, वो दूर करना मुश्किल है। ये हमला सिर्फ 28 लोगों पर नहीं पूरे देश पर है। उन कश्मीरियों पर भी है जो टूरिज्म सेक्टर के सहारे अपना घर चला रहे थे। लोग वहां नहीं जाएंगे तो उनका रोजगार भी जाएगा और सैकड़ों परिवारों पर इसका असर पड़ेगा। यानी जो कश्मीर बरसों बाद संभला था, जो फिर दरक गया।

कश्मीर की 12 लाख से ज्यादा बुकिंग कैंसिल- पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब तक 12 लाख से ज़्यादा बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं। ट्रेवल एजेंटों के पास कश्मीर की यात्रा को रद्द करने या आगे बढ़ाने के लगातार फोन आ रहे हैं। आतंकियों ने जिस तरह से सैलानियों को मारा, उससे लोगों में खौफ है। शायद अगले कुछ सालों तक कोई कश्मीर जाना चाहेगा। गुलमर्ग गोंडोला जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स ने 2024 में अकेले 103 करोड़ रुपये कमाए थे। लेकिन अब वो सभी जगह खाली हैं। पहलगाम के आस-पास के इलाकों में सुरक्षा सख्त कर दी गई।

एक झटके में सब तबाह हो गया- जम्मू-कश्मीर टूरिज्म विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में 1.13 करोड़ पर्यटक यहां पहुंचे थे। 2022 में ये आंकड़ा बढ़कर 1.88 करोड़ हुआ और 2023 में यह 2.11 करोड़ तक पहुंच गया। 2024 में रिकॉर्ड 2.36 करोड़ पर्यटक जम्मू-कश्मीर घूमने पहुंचे, जिसमें से 27 लाख पर्यटक अकेले कश्मीर आए। घाटी में होटलों की इतनी डिमांड हो गई थी, कि कई जगह पर्यटकों को प्राइवेट होमस्टे में ठहराया गया। गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम जैसे डेस्टिनेशन फिर से गुलजार हो गए थे। होटल कारोबार चरम पर था। गुलमर्ग को एशिया के टॉप स्की डेस्टिनेशनों में शामिल किया जा चुका था। लेकिन, एक झटके में सब तबाह हो गया।

टूरिज्म की इकोनॉमी में बड़ी हिस्सेदारी- जम्मू-कश्मीर टूरिज्म पॉलिसी 2020 के मुताबिक, टूरिज्म यहां के जीडीपीएस में लगभग 7 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है। 2018-19 में जम्मू-कश्मीर का अनुमानित जीडीपीएस 1.57 लाख करोड़ रहा, जिसमें टूरिज्म का हिस्सा करीब 11,000 करोड़ से अधिक बैठता है। 2019-20 में टूरिज्म का योगदान 7.84 प्रतिशत था, जो 2022-23 में बढ़कर 8.47 प्रतिशत तक पहुंच गया।

टूरिज्म से हर क्षेत्र में विस्तार

सरकार की योजना थी कि 2025 तक जम्मू-कश्मीर को भारत का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाए। इसके लिए हर साल 2,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं, बल्कि एडवेंचर टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, सैफरन टूरिज्म, हॉर्टी-टूरिज्म, हेरिटेज और कल्चरल टूरिज्म को भी तरजीह दी जा रही थी।

फल मंडी भी उफान पर

घाटी में सिर्फ टूरिज्म ही नहीं, बल्कि फल व्यापार भी तेजी से फला-फूला। खासकर सोपोर की फल मंडी, जिसे दिल्ली की आजादपुर मंडी के बाद एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फल मंडी माना जाता है। वहां 2024 में सालाना टर्नओवर 7,000 करोड़ तक पहुंच गया। कुपवाड़ा, बांदीपोरा, बारामूला और बडगाम जैसे जिलों के हजारों किसान और मजदूर इस मंडी से जुड़े हैं, जिनकी पूरी रोजी-रोटी इन मौसमी व्यापारों पर टिकी है।

पर्यटक यहां फिर से आने लगे थे

धीरे-धीरे कश्मीर एक नई पहचान की ओर बढ़ रहा था। घाटी को सिर्फ हिंसा और संघर्ष से जोड़कर देखने की सोच बदल रही थी। देश-विदेश के पर्यटक यहां फिर से आने लगे थे। लेकिन, पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले ने फिर से घाटी को वही पुराना खौफ याद दिला दी।

पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादी हमले का विरोध

भोपाल। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादियों द्वारा किए गए कायराना हमले के विरोध में मुस्लिम महिलाओं ने पाकिस्तान का झंडा जलाकर आंतकवाद मुर्दाबाद लिखित काले गुब्बारे हवा में छोड़ विरोध जताया।

विश्व टीकाकरण सप्ताह में दी जा रहे टीकों से रोकी जाने वाली बीमारियों की जानकारी

भोपाल में हर साल 60 हजार से ज्यादा बच्चों और गर्भवतियों को लगाए जा रहे टीके

भोपाल। टीकाकरण जागरूकता के लिए विश्व टीकाकरण सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है । जिसमें टीकाकरण की पहुंच एवं जागरूकता को बढ़ाने के लिए गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। सप्ताह के दौरान रिक्त उप स्वास्थ्य केंद्रों, कम उपलब्धि वाले वार्डों,उप स्वास्थ्य केंद्रों एवं हाईरिस्क क्षेत्र में आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन्म से लेकर 5 वर्षों के बच्चों की सूची तथा ड्यू लिस्ट अनुसार टीकाकरण किया जा रहा है। पैरी अर्बन एरिया एवं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के रहवासी परिवारों के बच्चों के टीकाकरण हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। मेडिकल ऑफिसर, एएनएम, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, सुपरवाइजर , आशा कार्यकर्ताओं का उन्मुखीकरण किया जा रहा है। स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, चौपाल व चौराहा, मंदिर ग्राम प्रवेश दीवार पर टीकाकरण संबंधी नारे लेखन करवाया जा रहा है। भोपाल जिले में पिछले साल 60275 बच्चों को टीके लगाए गए हैं जिसका कवरेज 105 प्रतिशत है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2026 तक खसरा और रूबेला के निर्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

खसरा और रूबेला संक्रामक रोगों के शून्य मामलों के लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए एम आर 1 एवं एम आर 2 अटीकाकृत बच्चों की जानकारी घर-घर जाकर ली जा रही है । जिले में 50789 बच्चों को एम आर 1 और 47928 बच्चों को एम आर 2 टीके लगाए गए हैं। प्रत्येक गर्भवती महिला को टी डी टीके का डोज सुनिश्चित करने के लिए टीकों का सत्यापन भी किया जा रहा है। मातृ एवं शिशु कार्ड में प्रविष्टियों की स्थिति भी देखी जा रही है । बच्चों के टीकाकरण से वंचित रहने की विस्तृत रूप से समीक्षा की जा रही है, ताकि कोई भी बच्चा इन टीकों से वंचित न रहे। कोविड-19 महामारी के संक्रमण की गंभीरता को कम करने में भी टीकाकरण ने अपनी भूमिका निभाई है। निजी क्षेत्रों में जिन टीकों की कीमत हजारों में है, वो सरकार निशुल्क लगवा रही है। आज टीकाकरण के द्वारा ही पोलियो, हेपेटाइटिस बी, टीबी, डिप्थीरिया, पर्टूटिस, टिटनेस, निमोनिया, डायरिया, खसरा ,रूबेला जैसी गंभीर एवं जानलेवा बीमारियों से बचाव हो रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ प्रभाकर तिवारी ने बताया कि 12 गंभीर बीमारियों से अपने बच्चों को बचाने के लिए समय पर टीके लगवाना हर माता-पिता का मूलभूत दायित्व है। पोलियो जैसी गंभीर बीमारी का उन्मूलन टीकाकरण के माध्यम से ही किया गया है। टीकों के द्वारा ही कई बीमारियों का उन्मूलन किया जा चुका है। जबकि कई जानलेवा बीमारियों से बचाव में भी टीके महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत हेपेटाइटिस बी, पोलियो ,बीसीजी, रोटावायरस, एफ आई पी वी, पीसीवी , पेंटावेलेंट, विटामिन ए, मीजल्स , रुबेला, डीपीटी, टी डी के टीके लगाए जा रहे हैं। ये सभी टीके शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों में निशुल्क लगाए जाते हैं।

विधायक भगवानदास सबनानी ने किया भूमिपूजन

भोपाल। दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 31 में 35 लाख रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री व विधायक भगवानदास सबनानी ने शनिवार को भूमि पूजन किया। क्षेत्र के तुलसी नगर, शिव नगर में सीसी रोड, नाली और पेवर ब्लॉक के कार्य किए जाएंगे। इस अवसर पर श्री सबनानी ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए हम सब जनप्रतिनिधि संकल्पित है, हमारी दक्षिण-पश्चिम विधानसभा में निरंतर विकास कार्यों लिए भूमि पूजन किया जा रहे हैं और निर्माण कर भी तेजी से हो रहे हैं, मैं जोन अध्यक्ष एवं पार्षद श्रीमती ब्रजुला सचान जी को जनमानस से जुड़े हुए विकास कार्यों की योजनाओं पर निरंतर कार्य करने के लिए बधाई देता हूं। क्षेत्र में निरंतर हो रहे विकास कार्यों की देखभाल की जवाबदारी भी आप सभी लोगों को करना है।

भोपाल। आर के फार्म निपानिया जाट पर हीरो बाइक की लाइव द थ्रिल लॉन्चिंग की। इस अवसर पर पार्षद कुसुम चतुर्वेदी एवं आयोजन समिति उपस्थिति रही।

ग्राम मुंडला में मनाया गया पंचायती राज दिवस

संत हिरदाराम नगर। वोडाफोन आइडिया फाउंडेशन एवं सोलिडरीडॉड संस्था के द्वारा चलाए जा रहे स्मार्ट एग्री प्रोजेक्ट के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुंडला में पंचायती राज दिवस मनाया गया। पंचायतीराज दिवस के उपलक्ष में सॉलिडरीडाड संस्था के द्वारा किसानों को पंचायती राज दिवस क्यों मनाया जाता है एवं पंचायत को पंचायतराज के अंतर्गत कौन-कौन से अधिकार प्राप्त है जानकारी दी गई। साथ ही किसान भाइयों के साथ पुनर्योजी खेती, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, पूर्णत: जैविक खेती पर चर्चा की गई। एवं ग्राम पंचायत सरपंच गांव के किसानों ने शपथ ली की वह धीरे-धीरे जैविक खेती करना प्रारंभ करेंगे एवं वन संरक्षण, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण करेंगे। एवं ग्राम पंचायत सरपंच ने आश्वासन दिया कि हमारी ग्राम पंचायत मुंडला सॉलिडरीडाड संस्था के द्वारा किए जा रहे किसान हितेशि कार्यों के लिए पंचायत संस्था का पूर्ण सहयोग करेंगी साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देगी।

आलोक सारस्वत की पत्नी का निधन

भोपाल। अत्यंत दु:ख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि श्री आलोक सारस्वत ,मध्य प्रदेश विधान सभा की धर्म पत्नी श्रीमती माधवी सारस्वत का आज दिनाँक 27 अप्रेल 2025 को हो गया है .जिनकी अंतिम यात्रा निज निवास छ्य -4/201 दानिश कुंज से दोपहर 12.45 बजे भदभदा विक्षाम घाट के लिए प्रस्थान करेंगी

विश्व डिजाइन दिवस - डिजाइन में रचनात्मकता, तकनीकी ज्ञान और समस्या समाधान कौशल का संयोजन होता है: योग गुरु महेश अग्रवाल

भोपाल। आदर्श योग आध्यात्मिक केन्द्र स्वर्ण जयंती पार्क कोलार रोड़ भोपाल के योग गुरु महेश अग्रवाल ने बताया कि डिजाइन का मतलब है किसी उत्पाद, सेवा या अनुभव को बनाने के लिए एक योजना या रूपरेखा तैयार करना । डिजाइन में रचनात्मकता, तकनीकी ज्ञान और समस्या-समाधान कौशल का संयोजन होता है। विश्व डिज़ाइन दिवस हर साल 27 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन इस बात को दर्शाता है कि डिज़ाइन हमारी दुनिया को कैसे बदल सकता है। डिज़ाइन का हमारे दैनिक जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है - जितना हम समझते हैं उससे कहीं अधिक। डिजाइन सोचने का एक तरीका है जो समस्याओं का समाधान करता है और जीवन को बेहतर बनाता है। यह नवाचार को जन्म देता है और सुंदरता पैदा करता है। विश्व डिज़ाइन दिवस हमें डिजाइनरों के

असाधारण कार्यों की सराहना करने का अवसर देता है । ये वे लोग हैं जो हमारे आसपास की दुनिया को आकार देते हैं। यह दिन हमें डिजाइन की शक्ति के बारे में सोचने और यह विचार करने का भी अवसर देता है कि हम इसका इस्तेमाल दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं । ये दिन सुंदरता और कार्यक्षमता का संगम है । डिजाइन न केवल चीजों को सुंदर बनाता है, बल्कि उन्हें अधिक कार्यात्मक और उपयोगी भी बनाता है। उदाहरण के लिए, एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया कुर्सी न केवल सुंदर दिखता है, बल्कि बैठने में भी आरामदायक होता है। डिजाइन का उपयोग समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, ग्राफिक डिजाइन का उपयोग सूचना को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के लिए किया जाता है, जबकि उत्पाद डिजाइन का उपयोग उपयोगकर्ताओं के जीवन को आसान बनाने वाले उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। अच्छा डिज़ाइन हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है।

विंध्याचल एकेडमी छात्रों और शिक्षकों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए भी निरंतर प्रयासरत

भोपाल। विंध्याचल एकेडमी, शिक्षा के क्षेत्र में केवल अकादमिक उत्कृष्टता तक सीमित नहीं रहती, बल्कि छात्रों और शिक्षकों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। यहाँ न केवल विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा दी जाती है, बल्कि शिक्षकों को भी समय-समय पर सॉफ्ट स्किल्स जैसे प्रभावी संचार, साक्षात्कार की तैयारी और समूह चर्चा में नेतृत्व कौशल विकसित करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अपने इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, विंध्याचल एकेडमी ने टोस्टमास्टर्स इंटरनेशनल के साथ मिलकर एक अत्यंत प्रभावी और व्यावहारिक सत्र का आयोजन किया, जिसने प्रतिभागियों के आत्मविश्वास और संवाद कला को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया। छात्रों और शिक्षकों दोनों के समग्र विकास के प्रति विंध्याचल एकेडमी की यह प्रतिबद्धता वास्तव में प्रेरणादायक है और उन्हें शिक्षा जगत में एक अलग पहचान दिलाती है इस अवसर पर विंध्याचल एकेडमी के प्रचार श्री मोहन राणा, मणि सक्सेना, अवंतिका शर्मा उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने पुलिस मुख्यालय पहुंच कर की कानून व्यवस्था की समीक्षा

अपराधियों पर अंकुश के लिए राज्य सरकार उठाएगी हर कदम

सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार की देर शाम पुलिस मुख्यालय पहुँचकर कानून व्यवस्था की स्थिति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में एक अच्छा निर्णय लेते हुए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। यह निर्देश पूर्व सरकारों में प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए गए जिनका जाने-अनजाने समुचित पालन नहीं हो रहा था, अब पुनः निर्देश जारी कर उचित व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। जनप्रतिनिधियों को यथोचित सम्मान देने की परम्परा और नियम दोनों ही हैं। राज्य सरकार इस संबंध में गंभीरतापूर्वक नियमों के पालन के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में नक्सल नियंत्रण के क्षेत्र में बेहतर कार्य हो रहा है। इसके साथ ही शिक्षण संस्थाओं में कोई अवैधानिक गतिविधियां न हो, इस दिशा में पुलिस को सक्रियता से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। नागरिकों के हितों की रक्षा और अपराध मुक्त समाज के निर्माण के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मध्यप्रदेश में कानून व्यवस्था (लॉ एंड ऑर्डर) की समीक्षा करते हुए गृह मंत्रालय से जारी निर्देशों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। प्रदेश में पाकिस्तानी वीजा धारक नागरिकों को चिन्हित कर गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गाइडलाइन अनुसार वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को प्रदेश से बाहर करना सुनिश्चित हो। मध्यप्रदेश में अध्यनरत जम्मू कश्मीर के छात्र-छात्राओं को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य में नक्सल नियंत्रण कार्यों की समीक्षा में आज बालाघाट को गंभीर नक्सली गतिविधियों वाले जिलों की श्रेणी से बाहर आने की उपलब्धि सामने आई है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी नक्सल अपराध श्रेणी में सुधार हो रहा है। प्रदेश में विगत डेढ़ वर्ष में दुर्दान्त नक्सलियों को मार गिराया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश नक्सलियों के पूर्ण खात्मे के लिए संकल्पबद्ध है। केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा दी गई डेडलाइन के अनुरूप आगामी वर्ष प्रदेश से नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। नक्सल उन्मूलन अभियान में नवीनतम तकनीक और संसाधन का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। साथ ही स्थानीय समुदाय को भी सुरक्षा तंत्र से जोड़ने के प्रयास किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अपराध नियंत्रण का कार्य पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक किया जा रहा है। समाज में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और अपराधी तत्वों के नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक प्रयास हो रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर लागू नए कानूनों के अनुरूप व्यवस्थाओं में भी आवश्यक सुधार किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासनिक अमले में बेहतर समन्वय है। नक्सल विरोधी अभियान और अन्य अपराधों पर अंकुश के लिए कार्य कर रहे पुलिस अधिकारियों और जवानों को आवश्यक प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है, जिसमें आउट ऑफ टर्म प्रमोशन और भत्ते इत्यादि पर समुचित ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस मुख्यालय में हुई बैठक में निर्देश दिए कि प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं पर नजर रखी जाए। उन्होंने भोपाल में कुछ युवकों द्वारा स्कूल, कॉलेज की कुछ छात्राओं से दुर्व्यवहार और अपराध से संबंधित खबरों पर चिंता व्यक्त की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिक्षण परिसरों अथवा इनके नजदीक कोई भी अवैधानिक गतिविधियां न हों, इन पर सतत् नजर रखी जाए और आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाए।

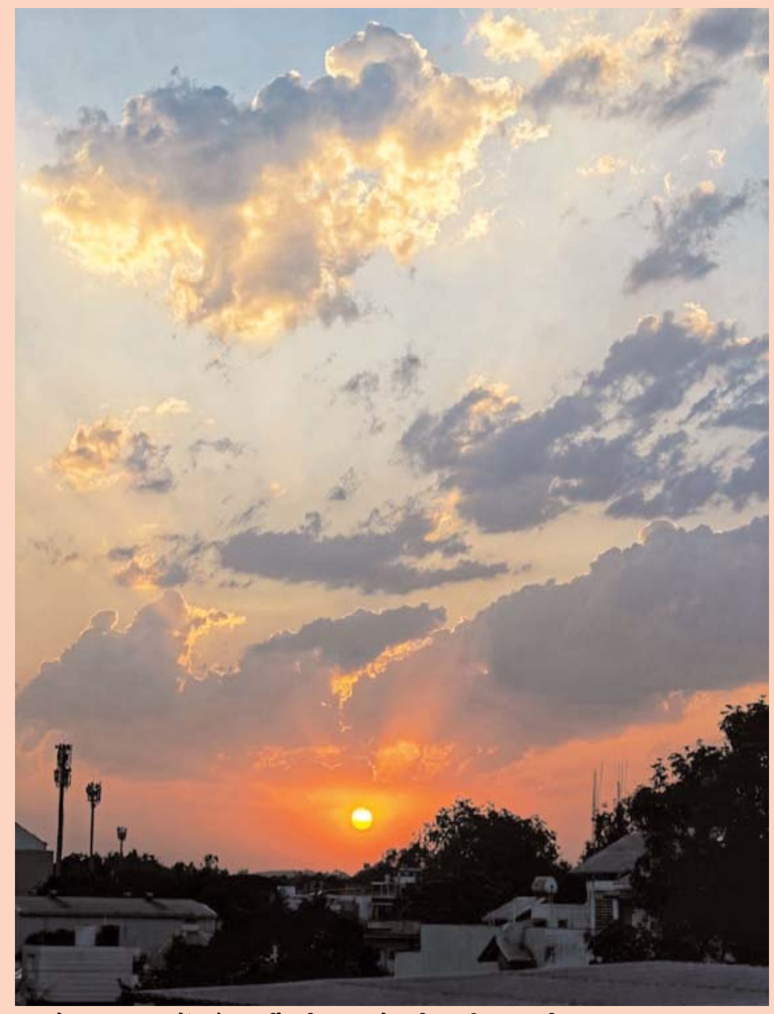

भोपाल। बादलों और गर्मी की तपन के बीच रविवार की सुबह का दृश्य।

स्वस्थ भारत की कल्पना प्रत्येक नागरिक के स्वस्थ रहने से होगी साकारः उप मुख्यमंत्री शुक्ल

भोपाल में शुरू हुआ पहला राष्ट्रीय मनोरोग सम्मेलन

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 में विकसित भारत के लिये जो विजन तैयार किया है, उसे प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ रखकर ही पूरा किया जा सकता है। इसके लिये हमें विभिन्न रोगों के साथ-साथ मनोरोग से भी छुटकारा पाना होगा। इस कार्य में मनोचिकित्सकों की अहम भूमिका रहेगी। उप मुख्यमंत्री शुक्ल भोपाल में मध्य भारत के पहले राष्ट्रीय मनोरोग सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। भोपाल में हो रहे 2 दिवसीय सम्मेलन में देशभर से 45 प्रमुख वक्ता शामिल हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि जीवन का पहला सुख निरोगी काया को माना गया है। आज के वैश्विक दौर में युवाओं में मानसिक तनाव मुख्य रूप से देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह व्यावहारिक जीवन में भारी चिंता, असीमित प्रतिस्पर्धा, असफल होने का डर और अत्यधिक मोबाइल समेत अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना प्रमुख है। ऐसे माहौल में मनोचिकित्सकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा कि दुनिया में हर वर्ष करीब 10 लाख लोगों की आत्महत्या के प्रकरण चिंता का विषय हैं। श्री शुक्ल ने कहा कि इन सब का उपाय भारत की प्राचीन परांपरा में समाहित है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि अनेक संस्थाएँ ध्यान और योग की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इन सबके और विस्तार की संभावनाएँ है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रत्येक जिला अस्पताल में मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के उपचार और सलाह के लिये विशेष कक्ष में सेवाएँ शुरू की है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा के साथ-साथ मनोरोगी के साथ लगातार संवाद भी जरूरी है। समाज में फोबिया, युवाओं में मानसिक बीमारियाँ, चिंता रोग, सिजोफ्रेनिया और ऑब्सेसिव-कम्पल्सिव डिसऑर्डर के रोगी सामने आ रहे है। इन सबसे निपटने में मनोचिकित्सक समर्पण भाव को प्रदर्शित करे।

कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. की संचालक डॉ. सलोनी सिडाना ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में मानसिक रोग के उपचार को विशेष स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि मनोरोगी के उपचार के पहले उसके परिवेश को समझा जाये तो समस्या का बेहतर तरीके से निदान किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में टेली-मानस हेल्पलाइन पर 24ङ्म7 पर निश्शुल्क परामर्श दिये जाने की व्यवस्था की गई है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने बताया कि इस हेल्पलाइन पर 3 लाख कॉल पर परामर्श दिया गया। कार्यक्रम को भोपाल गांधी मेडिकल कॉलेज की डीन डॉ. कविता सिंह, इंडिया एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट साइकियाट्री (आईएपीपी) के पदाधिकारी डॉ. आर.एन. साहू, डॉ. मृगेश वैष्णव ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. समीक्षा साहू ने किया।

राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरूआत में गांधी मेडिकल कॉलेज से इकबाल मैदान तक रैली निकाल कर मनोरोग के प्रति जन-जागरूकता और इससे सावधान रहने का संदेश दिया गया।

रीवा एवं इंदौर मेडिकल कॉलेज के उन्नयन का प्रस्ताव शीघ्र तैयार करें: शुक्ल

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य सेवाओं को जनसामान्य के लिए सुलभ, उच्च गुणवत्ता युक्त और व्यापक बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वरिष्ठ चिकित्सकों के अनुभव, आधुनिक मेडिकल कॉलेजों का सुदृढ़ आधार और समय पर नियुक्ति की प्रक्रिया से प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने भोपाल स्थित निवास कार्यालय में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े विभिन्न विषयों की गहन समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने प्रदेश में वरिष्ठ चिकित्सकों की विशेषज्ञता का लाभ उठाने के उद्देश्य से, उन्हें 70 वर्ष की आयु तक संविदा सेवा देने हेतु प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। प्रस्ताव कैबिनेट अनुमोदन के लिए शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि अनुभवी डॉक्टरों की सेवाएं प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों की गुणवत्ता में वृद्धि करेंगी साथ ही यह निर्णय चिकित्सकों की कमी की पूर्ति करने में भी सहायक होगा। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने रीवा और इंदौर के मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन का विस्तृत प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिये।

एआई से होगी अवैध खनन की निगरानी, प्रदेश की 7502 खदानों की हुई जियो टैगिंग

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर अवैध खनन भंडारण एवं परिवहन की रोकथाम के लिये ऑर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस (एआई)का उपयोग कर खनन निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश की समस्त स्वीकृत 7502 खदानों की जियो टेगिंग कर खदान क्षेत्र का सीमांकन किया जा चुका है। सैटेलाइट इमेज एवं रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी की सहायता से प्रदेश में हो रहे अवैध उत्खनन एवं भंडारण पर निगरानी रखी जायेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह प्रणाली खदान क्षेत्र के बाहर हो रहे अवैध उत्खनन का पता लगाने में सक्षम होगी। इसके अंतर्गत एक निश्चित समय अंतराल पर सतत रूप से प्राप्त सेटेलाइट इमेजेस का विश्लेषण कर सिस्टम द्वारा राज्य एवं जिला प्रशासन को अलर्ट भेजे जायेंगे। क्षेत्रीय अमले द्वारा मोबाइल ऐप से परीक्षण एवं निरीक्षण कर पोर्टल अथवा मोबाइल ऐप पर रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण पंजीबद्ध किया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर खदान या उसके बाहर ड्रोन सर्वे कर वॉल्युमेट्रिक एनालिसिस से वास्तविक उत्खनित मात्रा का पता लगाकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कर अर्थदण्ड अधिरोपित करने की परियोजना भी प्रक्रियाधीन है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खनिजों के अवैध परिवहन की रोकथाम के लिये नवीन तकनीक एआई पर आधारित मानव-रहित चेक-गेट पूरे प्रदेश में स्थापित किये जा रहे हैं। प्रदेश में 41 ऐसे स्थल चिन्हांकित किये गये हैं, जहाँ से खनिज परिवहन करने वाले वाहनों का सर्वाधिक आगमन होता है। चेक-गेट स्थापित करने के लिये टेण्डर के माध्यम से रेल टेल कॉर्पोरेशन को सर्विस प्रोवाइडर के रूप में चयनित किया गया है।

उन्होंने कहा कि पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में भोपाल के आस-पास 4 स्थानों पर ई-चेकगेट स्थापित किये गये हैं। निगरानी के लिये राज्य स्तर पर भोपाल में कमाण्ड एवं कंट्रोल सेंटर और जिला स्तर पर भोपाल एवं रायसेन में जिला स्तरीय कमाण्ड सेंटर स्थापित किया गया है। ई-चेकगेट में वेरीफोकल कैमरा, आर.एफ.आई.डी. रीडर, ऑटोमेटिक नम्बर प्लेट रीडर की सहायता से खनिज परिवहन में संलग्न वाहन की जाँच के प्रावधान हैं। प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत विभाग की गतिविधियों को ऑनलाइन करने के लिये एनआईसी द्वारा वेब पोर्टल (ई-खनिज) बनाया गया है। ई-खनिज पोर्टल को परिवहन विभाग के पोर्टल साथ लिंक किया गया है। इससे पट्टेदार/ट्रांसपोर्टर खनिज परिवहन करने के लिये ऑनलाइन वाहनों का रजिस्ट्रेशन ई-खनिज पोर्टल पर कर सकते हैं। डिजिटल इण्डिया अंतर्गत विभाग द्वारा ई-खनिज पोर्टल से खनिजों के परिवहन के लिये ऑनलाइन परिवहन पारपत्र (द्न-ञ्चक्र) की सेवाओं को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी पट्टेदार रॉयल्टी एवं अन्य राशि का भुगतान करने के बाद ई-टीपी प्राप्त कर सकता है। खनिजों के परिवहन में संलग्न वाहनों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश के 55 जिलों में ई-खनिज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ई-टीपी सेवाओं को लागू किया जा चुका है। इस व्यवस्था के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण की जानकारी एमआईएस रिपोर्ट के रूप में प्राप्त की जा रही है। ई-टीपी की व्यवस्था लागू होने से पट्टेदार द्वारा ऑनलाइन रॉयल्टी का भुगतान किया जा रहा है। इससे केशलैस ट्रॉन्जेक्शन की मंशा भी पूरी की गयी है। खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिये खनिज परिवहन किये जाने वाले वाहनों का ई-रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत विभिन्न आवेदनों को ऑनलाइन ई-खनिज पोर्टल के माध्यम से जमा करने की व्यवस्था लागू की गयी है। विभागीय पोर्टल द्वारा खनिज अन्वेषण एवं खदानों की जानकारी आमजन को उपलब्ध करायी जा रही है।

मेपकास्ट द्वारा नवप्रवर्तन को प्रोत्साहन देने के लिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में बौद्धिक संपदा अधिकार और इसकी उपयोगिता के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए मध्यप्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा सरोजिनी नायडू कन्या महाविद्यालय,शासकीय कमला नेहरू कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल, ओरियंट स्कूल एवं द आइकॉनिक स्कूल में 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया।

कार्यक्रम में रिसोर्स पर्सन के रूप में डॉ. अजय चौबे, श्री शैलेन्द्र कसेरा ने बौद्धिक संपदा के विविध पहलुओं जैसे कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क की गहन जानकारी दी। उन्होंने रोचक उदाहरणों से यह समझाया कि कैसे विद्यार्थी अपने नवाचार और मौलिक रचनाओं के ज़रिए पेटेंट प्राप्त कर सकते हैं और इससे आर्थिक लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने संबोधन में नवाचार, अनुसंधान और बौद्धिक संपदा संरक्षण के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने छात्रों को प्रोत्साहित किया कि वे अपनी कल्पनाशक्ति और सृजनशीलता को संरक्षित कर देश के विकास में योगदान दें।

कार्यक्रम में छात्रों ने बौद्धिक संपदा के महत्व को समझते हुए नवाचार करने का संकल्प लिया। सभी विद्यालयों के प्राचार्य सहित शिक्षकों ने परिषद के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम छात्रों में रचनात्मकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। इस अवसर पर परिषद के महानिदेशक डॉ. अनिल कोठारी ने नवाचार को बौद्धिक संपदा के रूप में पंजीयन कराने और उसके व्यवसायीकरण पर जोर दिया है।

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार नवाचार वर्ष 2025 के लिए कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

भोपाल। शासकीय सेवाओं में नवाचार एवं उत्कृष्ट कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष 'मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार (नवाचार)' प्रदान किया जाता है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए वर्ष 2024-25 में किये गए नवाचारों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गये हैं। आवेदन वेबसाइट www.awards.mp.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन किये जा सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। शासकीय सेवाओं में नवाचार एवं उत्कृष्ट कार्यों को बढ़ावा देने प्रदान किये जाने वाले वार्षिक 'मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार (नवाचार)' के लिए प्रदेश के शासकीय और सार्वजनिक संस्थानों के अधिकारी-कर्मचारी एक अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक किये गए नवाचारों के आधार पर आवेदन कर सकेंगे। पुरस्कार के लिए राज्य शासन के विभाग एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों के उल्लेखनीय नवाचारों को मान्यता दी जाएगी। पुरस्कार के लिए ऐसे कार्यों का चयन किया जाएगा, जिनसे जनसेवा में गुणवत्ता, दक्षता और नवाचार दृष्टिगोचर होता हो।

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार (नवाचार) महिला एवं बाल विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक समावेशन और समावेशी विकास के क्षेत्र में किये गये नवाचारों को प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक चयनित प्रविष्टि को एक लाख रूपये का नगद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार के विषय में अधिक जानकारी के लिए सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश से संपर्क किया जा सकता है। संबंधित सूचनाएं वेबसाइट www.awards.mp.gov.in पर भी प्रकाशित हैं।

5 दिवसीय ऑनलाइन अल्प-विराम प्रशिक्षण 28 अप्रैल से

भोपाल। राज्य आनंद संस्थान द्वारा 28 अप्रैल से 2 मई 2025 तक 5 दिवसीय ऑनलाइन अल्प-विराम प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इसके बाद 5 से 9 मई, 12 से 16 मई एवं 19 से 23 मई, 2025 तक ऑनलाइन अल्प-विराम प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य आनंद संस्थान श्री आशीष कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण में शासकीय एवं अशासकीय व्यक्ति पंजीयन कराकर भाग ले सकते हैं। अधिक जानकारी राज्य आनंद संस्थान की वेबसाइट www.anandsansthanmp.in से प्राप्त की जा सकती है।

भोपाल की पहली वाइट टॉपिंग सड़क कोलार में बनेगी

मंदाकिनी चौराहे से दानिश कुंज की फोर लेन सड़क होगी सीमेंट की

विधायक रामेश्वर शर्मा ने मुखर्जी नगर कोलार में किया निरीक्षण

सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

विधायक रामेश्वर शर्मा शनिवार को प्रात: 7 बजे तमाम प्रशासनिक अमले के साथ मुखर्जी नगर कोलार के निरीक्षण पर निकले इस दौरान उनके साथ एसडीएम कोलार, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, पुलिस एवं विद्युत विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। सर्वधर्म पुल से निरीक्षण प्रारंभ हुआ। इस दौरान श्री शर्मा ने जे के अस्पताल रोड का भी निरीक्षण किया श्री शर्मा ने बताया कि मंदाकिनी चौराहे से अग्रसेन चौराहा (दानिश कुंज) तक का मार्ग अधिकतम चौड़ीकरण के साथ पूर्ण सीमेंट कांक्रीट किया जाएगा। इस मार्ग में बाधित विद्युत पोल को शिफ्ट किया जाएगा। ज्ञात हो की लगभग 10 करोड़ की लागत से इस सड़क का निर्माण किया जाएगा यह सड़क भोपाल की पहली वाइट टॉपिंग तकनीक से बनायी जाने वाली सड़क होगी। निरीक्षण के दौरान विधायक रामेश्वर शर्मा का फोकस बरसात से पहले जर्जर सड़कों के मरम्मत के साथ नालो की सफाई पर रहा। श्री शर्मा ने कहा की जल भराव के क्षेत्रों को चिह्नित कर जल्द से जल्द निकासी के प्रबंध किए जाए।

ये निर्देश भी दिए: अग्रसेन चौराहे से गिरधर परिसर की सड़क का निर्माण भी जल्द प्रारंभ किया जाएगा। खाटू श्याम मंदिर की रोड का निर्माण बहुत जल्द प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई सहित कॉलोनी की अंदरूनी जर्जर सड़कों का निर्माण बरसात से पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए है। नालों का निर्माण भी बहुत तेजी से बरसात से पूर्व पूर्ण किए जाने के निर्देश भी दिए।

पीएम आवास भी पहुंचे मेंटेनेंस को लेकर निर्देश दिए

मुखर्जी नगर कोलार के सनखेड़ी में बने कुशाभाऊ ठाकरे आवासीय परिसर स्थित प्रधानमंत्री आवास में पेय जल, साफ़ सफाई, सुरक्षा आदि की समस्याओं के स्थाई निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। ज्ञात हो कि मेनेटेंस नहीं जमा होने से यहाँ के नागरिकों को अनेक असुविधा का सामना करना पड़ रहा था।

आतंक पर आर-पार की तैयारी, सिंधु से सीमा तक सख्ती, पाकिस्तान को भारत का कड़ा संदेश

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले का स्वरूप ऐसा है कि भारत सरकार के लिए इस मसले पर ठोस कार्रवाई करना वक्त की जरूरत है। इसलिए भारत ने इस बर्बर घटना के बाद सख्त कदम उठाते हुए अगर पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है तो यह स्वाभाविक है। यह जगजाहिर हकीकत है कि भारत में आतंकवादी गतिविधियों के पीछे पाकिस्तान की क्या भूमिका रही है। इसलिए भारत के सामने अब एक तरह की मजबूरी आ खड़ी हुई है कि वह आतंकवाद और उसे शह देने वाले देश के खिलाफ नीतिगत स्तर पर कोई ठोस कदम उठाए।

इसी क्रम में गुरुवार को भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध कई कड़े कदम उठाने की घोषणा की। इनमें पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा पर पाबंदी, दूतावास में राजनयिक कर्मचारियों की संख्या में कटौती, अटारी-वाघा सीमा को बंद करना और सबसे अहम छह दशक पुरानी सिंधु जल संधि के क्रियान्वयन को निलंबित करना शामिल है।

जाहिर है, भारत की ओर से आतंक के विरुद्ध उठाए गए ये कदम पाकिस्तान को नागवार गुजरेंगे, लेकिन सच यह है कि लंबे समय से भारत में आतंकवाद की समस्या को और ज्यादा जटिल बनाने में पाकिस्तान की जो भूमिका रही है, उसने कई स्तर पर मुश्किलें खड़ी की हैं।

दूसरी ओर, आतंकवाद को बढ़ावा देने में अपने भूमिका पर शर्मिंदा होने के बजाय पाकिस्तान इस मसले पर आमतौर पर अपनी हठधर्मिता ही प्रदर्शित करता रहा है। इस बार भी जब भारत ने कुछ सख्ती दिखाई तो हकीकत स्वीकार करने के बजाय पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई के तौर पर भारत के साथ द्विपक्षीय शिमला समझौते को निलंबित करने, हवाई क्षेत्र और सीमाओं को बंद करने जैसे कुछ कदम उठाने की घोषणा कर दी।

सवाल है कि ऐसा करके पाकिस्तान क्या साबित करना चाहता है। पहलगाम में आतंकी हमला आतंकवादियों के अपने एजंडे के लिए क्रूरता की हर हद को पार करने की मंशा का सबूत है। वरना क्या कारण है कि कश्मीर गए जिन पर्यटकों का उद्देश्य वहां घूमना-फिरना और प्रकृति के सौंदर्य के बीच खुशी के कुछ पल गुजारना था, उन्हें भी मार डालने में आतंकियों को कोई हिचक नहीं हुई।

इस हमले का एक सीधा असर जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर चोट भी है। सवाल है कि इस तरह की क्रूरता करके आतंकवादी किसके हित में काम कर रहे हैं। समय-समय पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत सबूतों के साथ आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान को कठघरे में खड़ा करता रहा है। मगर पाकिस्तान हर बार इसे महज आरोप बताता है। जबकि भारतीय सीमा में घुसपैठ से लेकर आए दिन होने वाले आतंकी हमलों में पाकिस्तान के संरक्षण के तथ्य सामने आते रहे हैं।

फिलहाल पाकिस्तान जल संकट से दो-चार है और ऐसे में अगर भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने की घोषणा की है तो इससे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ेंगी।

बंगाल का इतिहास कई सालों से रक्त रंजित राजनीति का ही रहा है। पहले कम्युनिस्ट सरकारें जिस ढर्रे पर चला करती थीं, ममता बनर्जी भले उनसे सत्ता छीनने में सफल हो गईं लेकिन ढर्रे में कोई बदलाव नहीं आया। बंगाल में अब सीधा मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच में है। मुसलमानों की आबादी चुनावी राजनीति में एक तरफा फैसला करती है। बंगाल में यह आबादी सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाने लगी है। इसमें फेर बदल तभी संभव होगा जब पूरा बंगाल हिंदू-मुस्लिम राजनीतिक ध्रुवीकरण का आकार ले पाएगा। वक्फ़ के नाम पर यह ध्रुवीकरण बहुत तेजी से हो रहा है।

धार्मिक आजादी, व्यक्तिगत या समाज-वादी

सरयूसुत मिश्रा

देश में एक तरफ हीट वेव चल रही है तो दूसरी तरफ धार्मिक आजादी का पॉलिटिकल वेव चल रहा है. हर तरफ धर्म और मजहब को बचाने के पैगाम गाये जा रहे हैं. सर्वोच्च अदालत से लगाकर सड़कों तक धार्मिक उन्माद की बातें हवा में तैर रही हैं.. !!

सारा मसला संशोधित वक्फ़ कानून से खड़ा हुआ है. विरोधी राजनीतिक दल और कुछ मुस्लिम संगठन इसे मजहब में हस्तक्षेप मानकर अदालत के साथ ही सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. वक्फ़ बचाओ सम्मेलन हो रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून के कुछ प्रावधानों पर सरकार से सफाई मांगी है जो अगली सुनवाई में सामने आएगी.

कानून के इस धर्म युद्ध में सब अपनी अपनी आहुतियां डाल रहें हैं. सर्वोच्च न्यायालय पर भी सवाल खड़े किये जा रहे हैं. प्रदर्शनों में मौलवी मौलानाओं की सरकार के खिलाफ़ जो भाषा सुनाई पड़ रही है, वह संविधान सम्मत तो नहीं है. वक्फ़ कानून के सहारे एक पक्ष मुस्लिम समाज में अमीर और गरीब के कल्याण की बात कर रहा है तो वही दूसरा पक्ष समाज को एकजुट कर सड़कों पर उतरने की बातें कर रहा है. बातें कब? भड़काऊ और गलत हो जाती हैं, यह मंच पर भाषण देने वाला शायद समझ नहीं पाता.

बंगाल तो हिंदू मुस्लिम राजनीति की प्रयोगशाला बना हुआ है. वक्फ़ विरोध के नाम पर मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी घटा है, उसकी राख इतनी जल्दी बुझने वाली नहीं है क्योंकि अगले साल वहां चुनाव होना है. तुष्टिकरण और ध्रुवीकरण का खेल चरम पर है. किसी एक पक्ष को दोष देना वाजिब नहीं होगा. हिंदुस्तान की धरती पर हिंदुओं का पलायन पाकिस्तान और बांग्लादेश की याद ताजा कर रहा है.

बंगाल का इतिहास कई सालों से रक्त रंजित राजनीति का ही रहा है. पहले कम्युनिस्ट सरकारें जिस ढर्रे पर चला करती थीं, ममता बनर्जी भले उनसे सत्ता छीनने में सफल हो गईं लेकिन ढर्रे में कोई बदलाव नहीं आया. बंगाल में अब सीधा मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच में है. मुसलमानों की आबादी चुनावी राजनीति में एक तरफा फैसला करती है. बंगाल में यह आबादी सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाने लगी है.

इसमें फेर बदल तभी संभव होगा जब पूरा बंगाल हिंदू-मुस्लिम राजनीतिक ध्रुवीकरण का आकार ले पाएगा. वक्फ़ के नाम पर यह ध्रुवीकरण बहुत तेजी से हो रहा है. राजनीतिक ध्रुवीकरण तक तो परिस्थितियों को डाला जा सकता है लेकिन जब यह स्थानीय स्तर पर बहुसंख्यक समाज द्वारा अल्पसंख्यक समाज की हत्या का कारण बन जाए, उनके घर जलाए जाने लगें, पलायन करना पड़े, शेल्टर होम में जाकर रहना पड़े, तब तो फिर हकीकत पर गौर करना ज़रूरी है.

मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की हत्या हुई. हिंदुओं को पलायन करना पड़ा. जब यह सब चरम पर था. इस बीच ममता बनर्जी ने कोलकाता में राज्य के इमामों को बुलाकर संवाद किया. किसी से भी संवाद बुरा नहीं है लेकिन इसके के पीछे जब वोट की ममता छुपी हो तब सारे प्रयास धूर्तता की नजर से ही देखे जाते हैं.

इमाम से ममत्व का प्रदर्शन और वहां दिए गए भाषण, घुमाफिरा कर यही संदेश दे रहे थे कि, वोट बैंक का समर्थन और एकजुटता बनी रहे. ममता ने तो यहां तक कह दिया कि, इस संविधान के तहत बनाए गए वक्फ़ कानून को वह बंगाल में लागू नहीं करेंगी. उनका यह दावा संविधान सम्मत नहीं है, फिर भी इमामों के सामने यह बात कहकर ही वह उनके प्रति अपने कमिटमेंट की मजबूती पेश कर रही हैं.

यही मजबूती दूसरे समुदाय पर हमलो को प्रेरित करती है. लगातार मांग हो रही है कि ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद जाकर हिंदू पीड़ितों से मिलना चाहिए. शेल्टर होम में जाकर हिंदू पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर राहत पहुंचानी चाहिए. ममता बनर्जी वहां जाएंगी जरूर लेकिन तब, जब वोट बैंक की ओर से यह संकेत मिलेगा कि हमारी मैसेजिंग अपडेट हो गई है, अब आप दूसरे समुदाय में अपनी पॉलिटिकल मैसेजिंग को अपडेट कर सकती हैं.

वक्फ़ की लड़ाई संविधान और कानून की लड़ाई है. इसका नतीजा सड़कों पर तो कभी नहीं निकल सकता है. सड़कों पर केवल राजनीतिक उपयोग हो सकता है. राजनीति में मुसलमान को वोट बैंक के रूप में उपयोग करने वाले राजनीतिक दलों को यह समझना पड़ेगा कि, आजादी के बाद उनकी रणनीतियों का ही दुष्परिणाम है कि, आज हिंदू ध्रुवीकरण राजनीति की हकीकत बन गया है.

इसको जितना ज्यादा बढ़ाया जाएगा वह हिंदू ध्रुवीकरण को यह और तेज करेगा. इससे आगे चलकर उनको नुकसान ही होगा. कानून की सीमा में ही ऐसे मामलों को सुलझाना बुद्धिमानी भरा कदम होगा.

संविधान में धार्मिक आजादी की व्यवस्था को लेकर चारो तरफ अज़ान पढ़ी जा रही है. मुसलमान हर प्रदर्शन में धार्मिक आजादी की बात कर रहे हैं. मुस्लिम समर्थक राजनीतिक दल भी इसी भाषा में बात कर रहे हैं. सबसे पहला सवाल धार्मिक आजादी व्यक्तिगत मामला है या समाजवादी?

अगर व्यक्तिगत है तो यह आजादी प्रत्येक नागरिक के लिए सुरक्षित है. ऐसा नहीं हो सकता कि किसी समुदाय विशेष के लिए धार्मिक आजादी है. वैसे तो धार्मिक आजादी का राग अलापने के लिए अल्पसंख्यक बनने का स्वांग रचा जाता है और जब राजनीति की बात आती है तो हिंदुओं में जातिवाद का जहर घोला जाता है.

अगर जातियों के हिसाब से हिंदू और मुसलमान को ही देख लिया जाएगा तो फिर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की सही स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी. अल्पसंख्यक जनसंख्या का केवल आंकड़ा अगर है तो फिर इसे सभी वर्गों पर लागू होना चाहिए.

धार्मिक आजादी के नाम पर किसी दूसरे नागरिक की धार्मिक आजादी को अगर कुचला जा रहा है तो क्या यह धार्मिक आजादी के प्रावधानों का दुरुपयोग नहीं है. धार्मिक आजादी के नाम पर पर्सनल कानून कैसे संविधान सम्मत हो सकते हैं?

अभी तो वक्फ़ पर इतना हंगामा हो रहा है. जब समान नागरिक संहिता पर सभी राज्यों में काम आगे बढ़ेगा तो फिर तो इस तरह की टकराहट और बढ़ सकती है. सबसे पहला सवाल यह है कि, सबको संविधान के हिसाब से व्यवस्था संचालित करने का कमिटमेंट पूरा करना होगा. धार्मिक आस्था व्यक्तिगत है, धार्मिक आजादी व्यक्तिगत है, लेकिन व्यवस्था में धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए. सभी धर्म के लोगों को समान रूप से संविधान और कानून के मुताबिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार मिलना चाहिए.

हिंदू, मुसलमान दोनों को ईमान से सजदा करना होगा. ईमान रहेगा तभी धर्म रहेगा. तभी राजनीति रहेगी. पावर के लिए ईमान से बेईमानी, कयामत तक पीछा नहीं छोड़ेगी.

जल संरक्षण: छोटे-छोटे प्रयास से होगी बड़ी बचत

(प्रवीण कक्कड़)

कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। यह बात सच हो या न हो, लेकिन इतना तो सच है कि पानी हमारे जीवन की सबसे बहुमूल्य जरूरत है। आज दिल दुखता है जब हम बड़े-बड़े जल संरक्षण के प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, लेकिन अपने दैनिक जीवन में छोटी-छोटी लापरवाहियों से हज़ारों लीटर पानी बर्बाद कर देते हैं।

यह सच है कि पानी अनमोल है, और इसकी कमी भविष्य के लिए एक गंभीर चुनौती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर और आपके परिवार के छोटे-छोटे प्रयास भी मिलकर कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं?

आज हम बात करेंगे उन नन्हे कदमों की, जिन्हें उठाकर आप अपने घर को जल संरक्षण का गढ़ बना सकते हैं। सोचिए, अगर हर गृहिणी, हर छात्र, हर कामकाजी व्यक्ति अपनी दैनिक आदतों में थोड़ा सा बदलाव लाए, तो हम सामूहिक रूप से कितना पानी बचा सकते हैं!

यह पहल अब हमारे हाथ में है। अब इंतजार करने का समय नहीं, बल्कि कुछ करने का समय है। आइए देखें, कैसे आपके घर के छोटे-छोटे कार्य एक बड़ी जल क्रांति ला सकते हैं:-

1. नल की चाबी आपके हाथ में

- ब्रश करते वक्त, शेविंग करते वक्त या बर्तन धोते वक्त नल को खुला छोड़ना अब पुरानी बात हुई। जब पानी की ज़रूरत न हो, तो नल को तुरंत बंद करें। याद रखें, एक मिनट में बहता हुआ नल कई लीटर पानी बर्बाद कर देता है।
- लीक होते हुए नल और पाइपों को अनदेखा न करें। एक छोटा सा रिसाव भी साल भर में हज़ारों लीटर पानी की हानि कर सकता है। तुरंत मिस्त्री को बुलाकर इसे ठीक करवाएं।

2. प्रकृति का उपहार - वर्षा जल संचयन

- अपनी छत या आँगन में बारिश के पानी को इकट्ठा करने का आसान तरीका खोजें। यह पानी आपके पौधों की प्यास बुझा सकता है, आपकी गाड़ी धो सकता है और घर के अन्य कामों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
- छोटे स्तर पर गड्ढे बनाकर या टैंक स्थापित करके आप इस अनमोल प्राकृतिक संसाधन का सदुपयोग कर सकते हैं।

3. नहाने का तरीका बदलें, पानी बचाएं

- शावर के नीचे घंटों खड़े रहना अब लग्जरी नहीं, बल्कि पानी की बर्बादी है। बाल्टी और मग का इस्तेमाल करें - यह न केवल पानी बचाएगा बल्कि आपको प्रकृति के करीब भी महसूस कराएगा।
- अगर शावर का उपयोग करना ही है, तो कम समय के लिए करें और लो-फ्लो शावर हेड का इस्तेमाल करें।

4. धुलाई में समझदारी

- कपड़े धोने की मशीन को तभी चलाएं जब वह पूरी तरह भरी हो। आधे भरे मशीन को चलाना पानी और बिजली दोनों की बर्बादी है।
- हाथों से कपड़े धोते समय भी नल को लगातार खुला न रखें। बाल्टी में पानी भरकर धोएं।
- बर्तन धोते समय पहले उन्हें सूखे कपड़े से साफ कर लें, फिर कम पानी में धोएं। सिंक में पानी भरकर धोने से भी पानी की बचत होती है।

5. पौधों को प्यार से पानी दें

- पौधों को पानी देने का सही समय सुबह या शाम है, जब वाष्पीकरण कम होता है।
- ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकों का उपयोग करें, जो सीधे पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचाती हैं और बर्बादी को कम करती हैं।

6. अपनी गाड़ी को भी सिखाएं जल संरक्षण का पाठ

- गाड़ी धोते समय पाइप का इस्तेमाल करने की बजाय बाल्टी में पानी भरकर धोएं।
- कभी-कभी सिर्फ कपड़े से पोंछकर भी सफाई की जा सकती है।

याद रखिए

- नल बंद रखना एक आदत है, जिसे हमें अपनाना है।
- बारिश का पानी प्रकृति का आशीर्वाद है, जिसे हमें सहेज कर रखना है।
- पानी की हर बूंद का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है।

सोचिए, अगर आपके पड़ोसी, आपके दोस्त और आपके रिश्तेदार भी इन छोटे-छोटे प्रयासों को अपनाने लगें, तो हम मिलकर कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं! यह सिर्फ पानी बचाने की बात नहीं है, यह भविष्य को सुरक्षित करने की बात है। हर एक बूंद कीमती है, और हर एक छोटा प्रयास मायने रखता है।

आइए, आज ही संकल्प लें कि हम अपने घरों से जल संरक्षण की इस मुहिम को शुरू करेंगे। अपने बच्चों को इसके बारे में सिखाएंगे और उन्हें जल योद्धा बनने के लिए प्रेरित करेंगे।

÷पानी बचाओ, भविष्य बचाओ!÷ यह सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक जीवनशैली है जिसे हमें मिलकर जीना है। आइए, छोटे-छोटे प्रयासों से एक बड़ी क्रांति लाएं और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी का खजाना सुरक्षित करें।

मदद बंद होने से फड़फड़ाया पाक, भारत के खिलाफ दी परमाणु हथियारों की धमकी

गोपेन्द्र नाथ भट्ट की त्वरित टिप्पणी

पड़ोसी पाकिस्तान के नापाक इरादों और उसके आतंकवादी गतिविधियों से बाज नहीं आने तथा हाल ही जम्मू कश्मीर के स्विटजरलैंड माने जाने वाले पहलगाम में निर्दोष और निहत्थे भारतीय एवं विदेशी सैलानियों को मौत के घाट उतारने की नृशंस और कायराना घटना के बाद भारत के सब्र का बांध अब टूट गया है। भारत द्वारा पहलगाम के दोषियों और इस साजिश में शामिल लोगों का दुनिया के अन्तिम कोने तक पीछा करते हुए उन्हें उनके कारनामों की सजा देने की घोषणा के साथ ही पहली बार पाकिस्तान के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए 65 पुरानी सिंधु जल संधि पर रोक लगाने के फैसले से पाकिस्तान फड़फड़ा रहा है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान को तब तक सिन्धु पानी की एक बूंद भी नहीं देगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देना जारी रखेगा।

पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकियों ने 26 निर्दोष और निहत्थे लोगों को उनका धर्म पूछ कर मार डाला,जिसमें करीबन सभी हिन्दू भारतीय पर्यटक थे। भारत ने अपने इस पहले बड़े कूटनीतिक फैसले में सिंधु जल संधि पर रोक लगाने का जो बहुत बड़ा एलान किया है,उससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी के पानी की एक-एक बूंद के लिए तरस जाना तय लग रहा है। साथ ही पाकिस्तान की खेती और उस पर निर्भर एवं आधारित उद्योगों के भी चौपट होने के पूरे आसार दिख रहें है। उसके अलावा अगले दो तीन महीनों में वहां भारी बाढ़ के खतरे से भी नहीं नकारा जा सकता है। कंगाली के कगार और आर्थिक बदहाली के हालातों में जी रहें पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए भारत का यह रामबाण और सिन्धु जल समझौते को रद्द करने के कठोर फैसले का यह कदम न केवल एक बहुत कड़ा राजनीतिक फैसला है बल्कि,एक बहुत बड़ा कुटनीतिक कदम भी है जिसे लेकर पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आ चुकी है। वह इसे एक प्रकार से ‘युद्ध की कार्रवाई’ बता रहा है। साथ ही उसने भारत पर परमाणु हथियारों से हमला करने की धमकी और चेतावनी भी दे दी है। इसके अलावा पाकिस्तान शिमला समझौते को समाप्त कर फिर से कश्मीर का राग अलापने की बात भी कर रहा है। हालांकि उसने भारतीय सिविल विमानों के अपने हवाई क्षेत्र के ऊपर से यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया है और सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी सैन्य गतिविधियां भी बढ़ा दी है।

कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमेरिका,रूस,यूरोप सहित विश्व के अधिकांश देशों द्वारा भारत के पीछे खड़े हो जाने से आर्थिक बदहाली से ग्रस्त पाकिस्तान अकेला पड़ गया है लेकिन उसके कंधे पर चढ़ भारत का एक और दुश्मन चीन अपने गलत इरादों को अमलीजामा पहनाने की कोशिश में लग गया है। कूटनीतिज्ञ बताते है कि पाकिस्तान को चीन द्वारा श्रेय मिलना ही भारत के खिलाफ उसके दुस्साहस का एक बड़ा कारण है। चीन पाक अधिकृत कश्मीर के रास्ते अपने आर्थिक गलियारे को बढ़ाने के बहाने पाकिस्तान के सहयोग से भारत के पश्चिमी हिस्से की भी घेराबंदी करना चाह रहा है।

भारत और पाकिस्तान ने 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ल्ड बैंक भी इस संधि का एक हस्ताक्षरकर्ता है। इस संधि का उद्देश्य सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी को दोनों देशों के बीच बराबर बांटना था। संधि के तहत, तीन पूर्वी नदियों ब्यास, रावी और सतलुज का पानी भारत को दिया गया और तीन पश्चिमी नदियों चिनाब, सिंधु और झेलम का पानी पाकिस्तान को दिया गया। इसके बाद ब्यास,रावी और सतलुज का पानी सूखे राजस्थान को भी मिलना शुरू हुआ तथा पाकिस्तान की सीमा से सटे पश्चिम राजस्थान के सीमावर्ती रेगिस्तानी जिलों के खेतों और लोगों के कंठ की प्यास बुझाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई जल परियोजना राजस्थान की इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मूर्त रूप में सामने आई।

आजादी के बाद सात दशक से भी अधिक समय तक पाकिस्तान की नापाक हरकतों के बाद भी भारत ने अपने थार रेगिस्तान प्रभावित इलाकों के बजाय पाकिस्तान को कभी भी पानी की आपूर्ति नहीं रोकी लेकिन,भारत द्वारा पहलगामआतंकी हमले के बाद अब सिन्धु नदी जल समझौता रद्द कर पाकिस्तान को पानी देना बन्द करने के भारत के कूटनीतिक फैसले से पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से के लोगों के प्यासे मरने के हालात पैदा होने का खतरा पैदा होने वाला है जोकि उसकी अकड़ निकालने और बदहाली के लिए एक कड़ा कदम साबित होने वाला है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को रोकने का यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी (सीएसएस) की बैठक में लिया है। पाकिस्तान पानी बंद,सीमा बंद और वीजा बंद के साथ ही राजनयिक सम्बन्ध बंद करने के कठोर भारतीय फैसलों से बुरी तरह से बौखला गया हैं।

उन्होंने बताया कि इसके लिए भारत सरकार तीन योजनाओं पर काम कर रही है। एक कम समय का प्लान,एक मध्यम अवधि का प्लान और एक लंबी अवधि का प्लान। इन योजनाओं से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि पाकिस्तान को पानी की सप्लाई न हो सके। सरकारी सूत्रों के अनुसार, भारत पाकिस्तान की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। इसमें कानूनी चुनौतियां भी शामिल हैं। सूत्रों ने कहा,अगर पाकिस्तान भारत के फैसले के विरुद्ध वर्ल्ड बैंक जाता है, तो उसके लिए भारत ने अभी से अपना जवाब एवं प्रतिक्रिया तैयार कर ली है। भारत उसका जवाब प्रभावी ढंग से देगा।

भारत-पाकिस्तान बंटवारे के बाद दोनों देशों की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिंधु जल संधि समझौता किया गया था। 19 सितंबर, 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत छह नदियों ब्यास, रावी, सतलुज, सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी के इस्तेमाल को लेकर नियम तय किए गए थे। इस समझौते के तहत पाकिस्तान को तीन पश्चिमी नदियों चिनाब, झेलम और सिंधु से संपूर्ण जल प्राप्त होता है। वहीं भारत को सतलुज, व्यास और रावी नदियों का जल प्राप्त होता है। विश्व बैंक की लंबी मध्यस्थता के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था।

आजादी के बाद पाकिस्तान के साथ 1965 और 1961 की और कारगिल जैसी कई जंग लड़ चुके भारत ने कभी भी इस समझौते को नहीं तोड़ा और न ही पाकिस्तान का पानी कभी रोका। हालांकि, लंबे समय से भारत में इस जल संधि को तोड़े जाने की मांग हो रही है। इस समझौते के लागू होने से पहले 1 अप्रैल 1948 को भारत ने दो प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया था,जिससे पाकिस्तानी पंजाब की 17 लाख एकड़ जमीन पानी को तरस गई थी।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब सिन्धु जल समझौते को पूरी तरह से रद्द करने के भारत के कठोरतम फैसले के बाद पाकिस्तान की कमर पूरी तरह तोड़कर रख देने को तैयारी है। दरअसल, पाकिस्तान का पंजाब और सिंध प्रांत पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से चिनाब, झेलम और सिंधु जैसी नदियों के पानी पर ही निर्भर है लेकिन अब पाकिस्तान को इन नदियों का पानी नहीं मिलने से पाकिस्तान की बदहाली और बढ़ने वाली है। इसके बावजूद यदि पाकिस्तान अपनी नापाक करतूतों को नहीं छोड़ता है और जंग की बात कर भारत के बांधों आदि पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की बात कर रहा है तो इससे बड़ा उसका और कोई दुर्भाग्य नहीं होगा क्योंकि न तो पाकिस्तान की मौजूदा सरकार के पास भारत के साथ युद्ध लड़ने की ताकत बची है और न ही खुद उसे अपने नागरिकों,पाक अधिकृत कश्मीर तथा बलूच वासियों और कश्मीर घाटी के लोगों का समर्थन और सहानुभूति भी प्राप्त नहीं है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक भरत पटेल द्वारा इंडिपेंडेंट प्रेस 11, प्रेस काम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल से मुद्रित तथा 226, एमपी नगर जोन-2, भोपाल से प्रकाशित। संपादक — भरत पटेल, प्रबंध सलाहकार — भारती पटेल, संपादकीय सलाहकार — विष्णु कौशिक, सलाहकार संपादक - स्मिता पटेल, स्थानीय संपादक —हाकम सिंह गुर्जर
प्रकाशन से संबंधित समस्त समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार। समस्त न्यायिक कार्यवाहियों के लिए क्षेत्राधिकार भोपाल न्यायालय का रहेगा। रजि. नं. भोपाल डिवी. 48 म. प्र. ई-मेल : dspbpl67@gmail.com, वेबसाईट: dainiksandhyaprakash.in

शिक्षा में राष्ट्रबोध पर विचार गोष्ठी आज

भारतीय शिक्षण मंडल के 56वें स्थापना दिवस पर होगा कार्यक्रम

विदिशा। भारतीय शिक्षण मंडल के 56वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में "शिक्षा में राष्ट्रबोध विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन आज होगा। सम्राट अशोक अभियांत्रिकीय संस्थान के स्मार्ट क्लासरूम में प्रातः 10 बजे से यह कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ वनिता वाजपेयी, विशिष्ट अतिथि शासकीय आदर्श महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ ब्रम्हदीप अलूने, मुख्य वक्ता संपादक एवं लेखक डॉ. सुदीप शुक्ल रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सम्राट अशोक अभियांत्रिकीय संस्थान के डायरेक्टर डॉ वाय. के. जैन करेंगे। इस आयोजन में नगर के प्राध्यापक, शिक्षक, बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी, मातृशक्ति, विद्यार्थी, युवा एवं गणमान्य नागरिक सम्मिलित होंगे।

भारतीय शिक्षण मंडल शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुनरुत्थान के उद्देश्य से कार्यरत है। इसकी स्थापना सन 1969 में हुई थी। संगठन भारत की एकात्म जीवनदृष्टि पर आधारित तथा देश की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अनुभूति से उपजी, राष्ट्र के समग्र विकास पर केंद्रित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पाठ्यचर्या, व्यवस्था तथा शिक्षणविधि के विकास आदि उद्देश्यों के साथ देशभर में कार्य करता है।

समझौते से विवाद सुलझाने में ना कोई जीतता है न कोई हारता है - प्रधान जिला न्यायाधीश आर्य

आष्टा। लोक अदालत आपसी विवाद को सुलझाने की एक अभिनव पहल है। लोक अदालत के माध्यम से यदि आप अपने प्रकरणों का समझौता करते हैं तो ना उसमें कोई जीतता है और ना कोई हारता है। वही आपसी मन मुटाव व बेर भी खत्म होता है। उक्त आशय के उद्गार प्रधान जिला न्यायाधीश प्रकाश चंद्र आर्य ने आष्टा न्यायालय में अधिवक्ता परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किये। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर प्रकाश चंद्र आर्य ने 10 मई 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में आष्टा न्यायालय में लोक अदालत के संबंध में चर्चा की। इस अवसर पर

न्यायाधीश विजय डांगी, न्यायाधीश महेश कुमार चौहान, न्यायाधीश विनिता गुप्ता, न्यायाधीश दीपेन्द्र मालू, न्यायाधीश नदीम जावेद खान, न्यायाधीश ऋचा जैन, न्यायाधीश ऋचा शर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी जीशान खान एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस आकाश अमलकर, तहसीलदार मुकेश कुमार सावले, नगर निरीक्षक आष्टा गिरीश दुबे, नगर निरीक्षक सिद्दीगंज राजू सिंह बघेल आदि उपस्थित रहे।

अभिभाषक संघ आष्टा सचिव कुलदीप शर्मा, उपाध्यक्ष लखनलाल खंडारे एवं सहसचिव बाबूलाल परमार एवं अभिभाषक संघ के सदस्यगण द्वारा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री प्रकाश चंद्र आर्य का स्वागत किया गया।

प्रधान जिला न्यायाधीश ने कहा की लोक अदालत के माध्यम से चेक बाउंस, बैंक वसूली प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, विद्युत चोरी प्रकरण, वैवाहिक विवाद के प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण और सभी प्रकार के सिविल व भूमि विवाद के प्रकरण रखे जायेंगे। जिसमें नगर पालिका के अंतर्गत जलकर, संपत्तिकर के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में नियम अनुसार छूट प्रदान की जावेगी। विद्युत के लंबित एवं प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में भी विशेष छूट घोषित की गई है।

उनके द्वारा अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण में अपेक्षित सहयोग प्रदान करने तथा घोषित छूटो का लाभ उठाने का आव्हान किया गया, ताकि पक्षकारों को शीघ्र एवं सुलभ न्याय प्राप्त हो सके।

अल्पसंख्यक कांग्रेस व जमीयत उलेमा ए हिंद के नेतृत्व में आतंकवाद का विरोध कर पुतला दहन किया

आष्टा। अल्पसंख्यक कांग्रेस व जमीयत उलेमा ए हिंद के नेतृत्व में आतंकवाद का विरोध कर पुतला दहन किया गया जिसमें मुख्य रूप से आतंकवाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए सभी ने विरोध में दो शब्द कहे प्रमुख रूप से तोसिफ उद्दीन जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस शहरयार चांद मियां जिलाअध्यक्ष जमीअत उलमा हिंद जाहिद गुड्डू शहर कांग्रेस अध्यक्ष फैज उद्दीन जिला अध्यक्ष खेल प्रकोष्ठ नवाब बेरी तहसील अध्यक्ष मुस्लिम त्योहार कमेटी खालिद पठान पूर्व उपाध्यक्ष न पा शेख रईस पार्षद प्रतिनिधि भैया एमपी पूर्व कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष रिज़वान माहिर यूथ कांग्रेस मुबारिक उद्दीन, असलम भाई आज़मभाई, अरबाज़ भाई, भाई शेख, रिज़वान, नसीर खान वा तमाम मुस्लिम समुदाय उपस्थित रहा।

जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत तालाब में चलाया श्रमदान

सिरोंज। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत शनिवार को स्थानीय तालाब ने श्रमदान किया गया। प्रशासन के आला अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से सभी ने करीब दो घंटे तक परिणाम कर तलब में बिखरे कचरे को साफ किया। इस दौरान एसडीएम स्वयं भी गंदगी को साफ करते हुए दिखाई दिए। इसके उपरांत स्थानीय बस स्टैंड परिसर पर जल गंगा संवर्धन अभियान के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जन जागरण कर रही कलाकारों की टीम के साथ पानी को बचाने एवं प्राचीन जल स्त्रोतों के संरक्षण की शपथ भी ली। इस दौरान एसडीएम हर्षल चौधरी ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन के निर्देश एवं स्थानीय विधायक उमाकांत शर्मा के मार्गदर्शन में हमने सिरोंज के प्राचीन बावड़ियों,तालाबों को जीर्णोद्धार कर भू जल स्तर को सुधारने की कार्य योजना बनाई है। इसी श्रृंखला में आज तालाब प्रांगड़ में हमने स्वच्छता अभियान चलाया है जो निरंतर चलत रहेगा। हमारा प्रयास हे कि यह तालाब परिसर सुरक्षित होकर एक सुंदर प्राकृतिक वातावरण देने वाला स्थान बने। इस अवसर पर प्रमुख रूप से नपाध्यक्ष मनमोहन साहू,स्वास्थ्य अधिकारी धीरज मैना सहित जनप्रतिनिधि, जागरूक नागरिकगण एवं स्वच्छता कर्मचारी मौजूद रहे।

कन्यादान विवाह के आयोजन को लेकर विधायक ने ली समीक्षा बैठक

सिरोंज। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 30 अप्रैल को होने वाले सामूहिक विवाह आयोजन की तैयारियों को लेकर विधायक उमाकांत शर्मा ने शनिवार को समीक्षा की। एसडीएम हर्षल चौधरी के मौजूदगी में हुई बैठक में विधायक शर्मा ने विवाह कार्यक्रम के आयोजक जनपद पंचायत की सीओ तथा नगरीय क्षेत्र में नगरपालिका सीएमओ से आयोजन की तैयारियों की जानकारी लेते हुए कहा कि आगामी सम्मेलन के लिए तीन सौ से अधिक जोड़ों ने पंजीयन कराया है। इन दिनों भीषण गर्मी का दौर चल रहा है ऐसे में विवाह एवं निकाह के लिए शामिल होने वाले वर वधुओं के साथ उनके परिजनों को असुविधाओ का सामना न करना पड़े। विधायक शर्मा ने विवाह में शामिल होने वाले घराती बारातियों को बैठने एवं शीतल पेयजल के इंतजाम करने के निर्देश दिए। विधायक शर्मा ने कन्यादान सम्मेलन के आयोजन में प्रशासनिक ड्यूटी निभाने वाले अधिकारी कर्मचारियों से आग्रह करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश सरकार का यह गरीब बेटियों के विवाह का पुण्य का आयोजन है इसे अपना मानकर भव्यता के साथ हम सबको मिलकर संपन्न करना है। इस दौरान प्रमुख से जनपद सीईओ वंदना शर्मा,स्वास्थ्य अधिकारी धीरज मैना सहित नपा के अधिकारी कर्मचारी एवं जनपद पंचायत के सचिवगण मौजूद रहे

पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे के साथ जलाया आतंकवाद का पुतला

ओबेदुल्लागंज (संवाददाता)। कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या को लेकर आक्रोश लगातार जारी है पहलगाम में हुई आतंकी घटना के विरोध में शनिवार को भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा की मौजूदगी में नगर के सीताराम चौराहे पर आतंकवाद का पुतला जलाया गया एवं कैंडल जलाकर दी मृतकों को श्रद्धांजलि जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, नगरवासी, व्यापारी पत्रकारगण शामिल रहे इससे पहले नगर के मुख्य चौराहे से आतंकवाद की विरोध प्रदर्शन रैली निकालकर पाकिस्तान मुर्दावाद आतंकवाद मुर्दावाद के नारे लगाए गए। इस दौरान जनसमूह को संबोधित करते हुए विधायक पटवा ने कहा पहलगाम में हुई आतंकी घटना सभी के मन को व्यथित करने वाली है इसका संपूर्ण देश में कड़ा विरोध होना चाहिए और हम आशा करते है कि सरकार आतंकवाद के सफाये हेतु जल्द से जल्द निर्णायक कार्यवाही करे धर्म के नाम पर आतंक फैलाने वालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह और हमारी सरकार कड्री सजा दिलवाएगी इस मोंके मौके पर राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारी, पत्रकारगढ़, स्थानीय नागरिक, प्रशासनिक अधिकारी आदि लोग शामिल हुए।

जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले के विरोध में आष्टा बंद रहा निकाली रैली आतंकवाद पर मौन आक्रोश

आष्टा। शुक्रवार को संपूर्ण नगर बन्द रहा शहर के किराना ,होटल, इलेक्ट्रॉनिक सहित संपूर्ण दुकानें बंद रही दुकान बंद रहने से लोग चाय पान को भी तरस गए सबसे ज्यादा बस स्टैंड पर यात्रीयो को परेशानी उठाना पड़ी उन्हें बस स्टैंड पर कुछ भी सामान नहीं मिला यहां तक की चाय के लिए भी तरस गए। बता दे की जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले के विरोध में आज शहर बन्द का आह्वान व्यापारी एसोसिएशन ने किया था और इसका पूरे शहर में व्यापक असर देखा गया शहर के पुराना भोपाल इंदौर मार्ग अलीपुर, भोपाल नाका, सब्जीमंडी, बस स्टैंड, बुधवारा,बड़ा बाजार , कन्नौद मार्ग सहित संपूर्ण नगर बन्द नजर आया। व्यापारी एसोसिएशन ने शहर में जुलूस भी निकाला और लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से बन्द का आह्वान किया व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष रूपेश राठौर ने बताया कि पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकियों ने हमला किया था जिसमें हमारे निर्दोष लोग मारे गए हम चाहते हैं कि आतंकियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि दूसरी बार ऐसे हमले न हो सभी ने इस कायराना पूर्ण किए गए नरसंहार की कड़े शब्दों में निंदा की है। आज के आष्टा बंद में नगर के नागरिक, सामाजिक संगठन, युवा ,महिला संगठन, व्यापारी ,जनप्रतिनिधियों ने सहभागिता की।

निर्माण कार्य में धीमी गति होने पर कलेक्टर ने कई ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के दिए निर्देश

सागर कबरई प्रोजेक्ट अंतर्गत एकत्र हुए बैंक खातों में मुआवजा राशि भेजने के निर्देश

छतरपुर। कलेक्टर पार्थ जैसवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में निर्माण कार्यो को समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में डिप्टी कलेक्टर विशा माधवानी, ईई पीडब्ल्यूडी आरएस शुक्ला, ईई डब्ल्यूआरडी लता वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर श्री जैसवाल ने एनएचएआई, पीएम जीएसवाई, सेतु निर्माण, लो.नि.एनएच, डब्ल्यूआरडी, पीआईयू, पीडब्ल्यूडी छतरपुर, सीएम राइज विभागों के निर्माण कार्यों की समीक्षा की।कलेक्टर श्री जैसवाल ने एनएचएआई अंतर्गत सागर कबरई प्रोजेक्ट में पैकेज 3 एवं पैकेज 4 में बड़ामलहरा, बिजावर, महाराजपुर, छतरपुर में एकत्र हुए खातों की जानकारी लेते हुए अंशनिर्धारण कराने एवं शीघ्र भुगतान कराने के निर्देश दिए।पीएम जीएसवाई अंतर्गत बड़ामलहरा में रामटोरिया से घुवारा, बमनौरकला से घुवारा के शेष रोड निर्माण के कार्य को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए।

साथ ही प्रगतिरत पुलों की समीक्षा करते हुए केल नदी ब्रिज की प्रगति, जियो टैग हैबिटेशन, संपर्कता सर्वे में कनेक्टेड, अनकनेक्टेड हैबिटेशन लिस्ट की भी समीक्षा की।

कलेक्टर श्री जैसवाल ने लोक निर्माण (सेतु निर्माण) विभाग की बारीगढ़- गहवरा-गौरीहार मार्ग में केल नदी पर पुल निर्माण की भौतिक प्रगति में गति बढ़ाने के निर्देश दिए एवं बड़ामलहरा कायन मार्ग में काठन नदी पर पुल निर्माण में धीमी प्रगति होने पर अष्टविनायक कंपनी के ठेकेदार को टर्मिनेट करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने लो.नि.(राष्ट्रीय राजमार्ग) के अंतर्गत हरपालपुर-बायपास मार्ग के निर्माण की भौतिक प्रगति में शेष डब्ल्यूएमएम के काम समय सीमा में न होने एवं धीमी प्रगति पर इंफ्राकोन अहमदाबाद कंपनी के ठेकेदार को नोटिस जारी करने एवं पेनाल्टी अधिरोपित करने के लिए एसडीओ एनएच को निर्देश दिए। इसके अलावा गुलगंज से अमानगंज मार्ग में बराना नदी से केन नदी के कार्य में धीमी प्रगति होने पर संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।जल संसाधन विभाग अंतर्गत कलेक्टर ने काठन बृहद परियोजना, गढ़ी सेमरा तालाब, पिपरिया तालाब की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए भू अर्जन करने के लिए कहा एवं नेगुवा तालाब में गति बढ़ाने के लिए कहा। वहीं तेंदुआ नाला तालाब के संबंध में संबंधित एसडीएम एवं तहसीलदार से अतिक्रमण मुक्त की कार्यवाही के लिए भी कहा। कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग भवन नौगांव पीआईयू विभाग के प्रगतिरत कार्यों में बछरावनी में हाई स्कूल निर्माण में धीमी प्रगति होने पर मारुति कनस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के संबंध में नोटिस देकर 7 दिवस में जवाब लेने के ईई पीआईयू को निर्देश दिए। साथ ही बछौन में उप तहसील के निर्माण पूर्ण होने पर जल्द लोकार्पण कराने के निर्देश दिए। बड़ामलहरा में 2 नवीन न्यायालय भवन निर्माण में धीमी प्रगति पर बैंक कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अधूरी सड़क बनी ग्रामीणों के लिए मुसीबत - प्रशासन मौन

बैरसिया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सोनकच्छ जोड़ से पीपलखेड़ी तक 2022 में सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र को बेहतर आवागमन की सुविधा से जोड़ना था। प्रारंभिक चरण में कुछ डामरीकरण भी किया गया लेकिन उसके पश्चात निर्माण कार्य पूरी तरह बंद कर दिया गया है। वर्तमान स्थिति यह हे कि आटे में नमक जितना काम कर ठेकेदार महोदय महीनों तक लापता हो जाते हैं, कई किलोमीटर में न डामरीकरण किया गया, न समतलीकरण, न पुलियों का निर्माण हुआ और न ही किसी अन्य प्रकार का सुधार कार्य आज दिनांक तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है।

यह मार्ग विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यह लगभग 15 गांवों को सीधे राजधानी के मुख्य मार्ग (भोपाल-बेरसिया) से जोड़ता है, जो क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। इसके बावजूद इस सड़क की अनदेखी प्रशासन की गंभीर

लापरवाही को दर्शाती है।सड़क पर बिछी गिट्टी में आए दिन दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया वाहन फंस जाते हैं। ग्रामीणजन भारी मशक्कत के बाद इन वाहनों को निकाल पाते हैं। यह स्थिति न केवल आवागमन को बाधित करती है एवं प्रतिदिन दुर्घटना का कारण बनती है जिससे जान-माल की हानि की आशंका भी बबनी रहती हे। बरसात के मौसम में यह मार्ग दलदल और गड्ढों में तब्दील हो जाता है, जिससे स्कूली बच्चों, किसानों और आम जनता को अत्यधिक परेशानी होती है। स्थानीय नागरिकों द्वारा कई बार शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, किंतु प्रशासन और संबंधित विभाग अभी भी मौन हैं।

स्थानीय नागरिकों की प्रमुख मांगें

1. अधूरे सड़क निर्माण को तत्काल प्रभाव से पुनः शुरू किया जाए। 2. निर्माण की गुणवत्ता की जांच हेतु स्वतंत्र समिति गठित की जाए। 3. जिम्मेदार ठेकेदार और अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही की जाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है, परंतु ऐसी लापरवाहियां इस उद्देश्य को ही विफल कर रही हैं।

विश्व मलेरिया दिवस पर रैली निकालकर आमजनों को मच्छर से बचने की दी जानकारी

छतरपुर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल के आदेशानुसार जिले में विश्व मलेरिया दिवस का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें छतरपुर जिले के समस्त ब्लॉकों में शुक्रवार को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। जिसमें जिला एवं ब्लॉक स्तर पर मलेरिया रेली एवं आशाओं को मलेरिया से निपटने के लिए आवश्यक जानकारी दी गई, जिससे वो अपने ग्रामों को मलेरिया से मुक्त कर सकें। सीएमएचओ छतरपुर द्वारा हरी झंडी दिखा कर मलेरिया की कार्यकर्ताओं को समस्त वार्डो में प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया। मलेरिया से पीड़ित रोगियो की उनके घर पर रैपिड डाग्नोसकिट से जॉच की जायेगी। एवं पानी में लार्वा की पहचान आम जनता को वर्षा ऋतु आने के पूर्व सावधानी एवं बचाव के सबंध में जानकारी दी जायेगी। जिसमें घरो के आस पास बरसात का पानी जमा न होने दें, घर के छत पर रखे मटके, गमले, बैकार टायर, फुल दान, आदि को उल्टा करके रखे, सप्ताह में एक बार घर के कूलर, पानी की टंकी मटके, होदी का पानी खाली करके सुखा कर पुनाः भरें,घर के आस पास जमा पानी में जला हुआ ऑयल डालें,

सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें, सोते समय पूरे बाहो के कपड़े पहनें, किसी भी व्यक्ति को बुखार आने पर अपनी जॉच कराये एवं निःशुल्क उपचार पायें, उपचार की सुविधा समस्त शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क की जाती है एवं खाली पेट दवा का सेवन न करें।

इस दौरान डॉ आर.पी. गुप्ता मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी एवं सहायक मलेरिया अधिकारी एस.एल. अहिरवार, जे.एम.आई. दिनेश कुमार पटैरिया एवं समस्त मलेरिया एवं फायलेरिया स्टॉफ उपस्थित रहा। मलेरिया का उपचार एवं जॉच सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में निःशुल्क किया जाती है।

संविधान के पथ पर चलकर बाबा साहब को सम्मान देती है भाजपा

मण्डला। जिले में शुक्रवार को नगर पालिका टाउन हॉल में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ भीमराव अंबेडकर पर सम्मान सभा व विचार गोष्ठी का आयोजन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया।यहां मुख्य अतिथि के रूप जनजातीय कार्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके,भाजपा जिला अध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा, नगरपालिका अध्यक्ष विनोद कछवाहा एवं वन विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी एसएस उद्दे मुख्य रूप से उपस्थित रहे।कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता,

डॉ भीमराव आंबेडकर,डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तैल्य चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित से की गई।मंचासीन मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री द्वारा पगड़ी पहनाकर कर स्वागत किया गया।वहीं कैबिनेट मंत्री श्रीमती उईके ने शाह का शॉल श्रीफल से स्वागत किया।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री शाह ने कहा कि भीमराव अंबेडकर सामाजिक समरसता, न्याय,भाईचारा,बंधुत्व और संविधान निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान है जो हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देती है।हमें डॉ.अम्बेडकर के मार्ग पर चलकर उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए।उन्होंने ने कहा कि बाबा साहब का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारतीय रिजर्व बैंक है की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान रहा है क्योंकि वे एक अर्थशास्त्री थे।इसलिए उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने लोगों को कृषि क्षेत्र और औद्योगिक गतिविधियों के विकास के लिए प्रेरित किया उन्होंने लोगों को

विचार गोष्ठी कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री कुंवर विजय शाह

बेहतर शिक्षा और सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए भी प्रेरित किया दलित बौद्ध आंदोलन उनसे प्रेरित था।मंत्री श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया जिनमें से एक नाम भीमराव अम्बेडकर का भी नाम है।संविधान निर्माता डॉ भीमराव अम्बेडकर की संघर्ष गाथा भारत के युवाओं को प्रेरित करती रहेगी।डॉ भीमराव अम्बेडकर एक दलित समुदाय से आते थे जिन्होंने कर्मों से अपनी पहचान को सिद्ध किया और भारत के समस्त नागरिक को एक स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार दिया जिससे जातिवाद भेदभाव छुआछूत को खत्म किया और भारत देश को एक नई उपलब्धि मिली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस महान नेता की हमेशा अवहेलना की है।वहीं भाजपा ने देश की इस महान विभूति को समय के साथ सम्मान दिया और भारत रत्न से सम्मानित भी किया उन्होंने इस दौरान आतंकवाद पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि आतंकवादियों से भारत देश डरने वाला नहीं है जिस तरह की कायराना हरकत की गई है उसकी पूरे देश में निंदा हो रही है।वही उन्होंने मंच से कहा कि मंडला में ट्राइबल डी मार्ट खोला जायेगा।जो कि आदिवासी महिलाएं संचालित करेंगी और यहां पर सभी दैनिक उपयोग की सामग्री सस्ते दामों पर उपलब्ध होगी। उन्होने कहा कि भाजपा सरकार आम जनता की सरकार है जिसका उद्देश्य केवल विकास है।वहीं पीएचई कैबिनेट मंत्री श्रीमती उइके ने कहा कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने सदैव समाज के कमजोर, पिछड़े एवं वंचित वर्गों के अधिकारों और उनके उत्थान के लिए संघर्ष किया है।सामाजिक भेदभाव और असमानता जैसी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया।उन्होंने कहा कि डॉ.अम्बेडकर के विचार हमें समानता,न्याय और बंधुत्व की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं।उनके पदचिन्हों में चलकर हम समतामूलक एवं न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में अपना योगदान दें।भाजपा सरकार ने बाबा साहेब को भारत रत्न दिया और पंचतीर्थ विकसित किए।संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता और न ही इससे छेड़छाड़ कर सकता है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा ने कहा कि बाबासाहेब अंबेडकर के नाम से मशहूर बीआर अंबेडकर एक अर्थशास्त्री,राजनीतिज्ञ और समाजसुधारक थे जिन्होंने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी जिन्हें उस समय अछूत माना जाता था।भारत के संविधान के प्रमुख निर्माता अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों और मजदूरों के अधिकारों की भी वकालत की स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में पहचाने जाने वाले अंबेडकर का भारतीय गणराज्य की संपूर्ण अवधारणा के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है।मंच का संचालन अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष इंजी जुगल किशोर बघेल के द्वारा किया गया।वहीं आभार प्रदर्शन बसंत चौधरी के द्वारा किया गया।

बजाज आलियान्ज़ जनरल इंश्योरेंस ने क्लाइमेटसेफ पेश किया मौसम जनित जोखिमों के खिलाफ तुरंत क्लेम देने और मनमाफिक सुरक्षा देने वाला

पुणे, एजेंसी। भारत की प्रमुख निजी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में से एक बजाज आलियान्ज़ जनरल इंश्योरेंस ने क्लाइमेटसेफ नामक एक नया बीमा प्रोडक्ट लॉन्च किया है। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए, यह प्रोडक्ट उन लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है जो इसके प्रभावों से सबसे ज्यादा जद में आते हैं। यह बीमा विशेष रूप से खुदरा ग्राहकों, ऑफिस जाने वालों, ऑटो/टैक्सी चालकों, खुदरा दुकान मालिकों, डिलीवरी एजेंटों, घरेलू सेवा देने वाले प्रोफेशनल, गिग वर्कर्स, घरों में रहने वालों और कार्यक्रमों में भाग लेने वालों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिन्हें ज्यादा गर्मी, ठंडी लहरों और भारी बारिश जैसी जलवायु घटनाओं के कारण इनकम में कमी या खर्चों में वृद्धि का सामना करना पड़ता है।

क्लाइमेटसेफ इंश्योरेंस में उन स्थितियों को कवर किया गया है जिनमें अत्यधिक गर्मी के कारण बढ़े हुए बिजली बिल, यात्रा में अप्रत्याशित खर्च, खराब मौसम के कारण ग्राहकों की संख्या में कमी से बिक्री में गिरावट, बाढ़ के कारण सप्लाई चेन में देरी, लंबे समय तक बारिश से होने वाले रिसाव, भारी बारिश के कारण दुर्घटनाएं, गंभीर मौसम के कारण डेली वेज वर्कर्स के इनकम में नुकसान, बाढ़ और गर्मी की लहरों से घरेलू सामानों की क्षति, और खराब मौसम के कारण प्रोग्राम का कैन्सल हो जाना शामिल हैं। क्लाइमेटसेफ एक नया और आसान बीमा प्रोडक्ट है, जिसे ग्राहक साल में कई बार खरीद सकते हैं। इसमें क्लेम बिना किसी ज्यादा सूचना और कम से कम डॉक्युमेंट्स के साथ ऑटोमैटिक सात दिनों के भीतर निपटा दिए जाते हैं। यह बीमा प्रोडक्ट वास्तविक समय के मौसम डेटा के आधार पर प्रीमियम और कवरेज प्रदान करता है। ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार जोखिम स्थान, जोखिम अवधि (1 दिन से 30 दिन तक), मौसम जोखिम (अत्यधिक बारिश, कम तापमान, उच्च तापमान) और बीमित राशि का चयन कर सकते हैं। क्लाइमेटसेफ की घोषणा पर बोलते हुए बजाज आलियान्ज़ जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और सीईओ डॉ. तपन सिंघल ने कहा, जलवायु परिवर्तन से हर किसी का सामना होता राहत है। बेशक यह हमारे रोजमर्रा के जीवन को अक्सर मुश्किल भरे तरीकों से प्रभावित करता है। मौसम में उतार चढ़ाव के कारण फ्लाइट के कैन्सल होने से लेकर लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन और दैनिक यात्राओं में देरी तक, और जलवायु से संबंधित घटनाओं का फाइनैन्शल और ईमोशनल प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हम बजाज आलियान्ज़ जनरल इंश्योरेंस के लोग मानते हैं कि इससे निपटने के लिए निर्णायक कदम उठाने का समय आ गया है। क्लाइमेटसेफ इंश्योरेंस त्वरित वित्तीय राहत प्रदान करता है, क्योंकि यह पहले से तय मापदंडों के आधार पर ऑटो मैटिक पेमेंट कर बीमा कर्ता को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है, जिससे उनकी तत्कालिक जरूरतों को मैनेज करने में सहूलियत मिलती है। यह पारंपरिक बीमा की तुलना में अधिक किफायती है, क्योंकि इसमें प्रशासनिक लागतें कम होती हैं।

रामराज कॉटन ने अभिनेत्री मीनाक्षी चौधरी को मृथु टॉवल के लिए ब्रांड एंबेसडर बनाया

नई दिल्ली, एजेंसी। पारंपरिक और एथनिक कपडों के लिए भारत के प्रमुख ब्रांड रामराज कॉटन ने अभिनेत्री मीनाक्षी चौधरी को अपने नए लॉन्च किया गया प्रीमियम टॉवल रेंज, मृथु टॉवल के लिए ब्रांड एंबेसडर के रूप में घोषित किया है । प्रीमियम होम टेक्सटाइल सेगमेंट में अपनी शुरूआत करता हुआ, मृथु टॉवल कलेक्शन में चार सोची-समझी श्रेणियों में 100त्न प्रीमियम कॉटन और बांस के रेशों से तैयार की गई विलासिता, कम्फोर्ट और पर्यावरण के प्रति जागरूक डिज़ाइन का मिश्रण हैं। ब्रांड के पहले महिला के चेहरे के रूप में, मीनाक्षी चौधरी एक सुंदर और समकालीन आकर्षण लेकर आई हैं, जो नए ब्रांड के लिए नए अध्याय का प्रतीक है। यह घोषणा रामराज कॉटन के प्रबंध निदेशक श्री बी आर. अरुण ईश्वर ने की । मीनाक्षी चौधरी के द्वारा 360 - डिग्री अभियान जल्द ही टेलीविजन, डिजिटल, प्रिंट और रीटेल प्लेटफार्मों पर लॉन्च किया जाएगा, जो ब्रांड के गुणवत्ता, कम्फोर्ट और सांस्कृतिक गौरव के कालातीत मूल्यों को उजागर करेगा । मृथु टॉवल संग्रह में मॉर्डन लैफ़ स्टैल के अनुरूप चार सोच-समझकर डिज़ाइन की गई चार श्रेणियाँ हैं- सिग्नेचर संग्रह, इटालियन और जर्मन सौंदर्य शास्त्र से प्रेरित हैं, जिसमें 32 प्रीमियम कॉटन बुनाई पैटर्न प्रदर्शित किए गए हैं जो उच्च अवशोषण, रंग प्रतिधारण और कोई सिकुड़न नहीं होने का वादा करते हैं । द बेंबू टॉवल, यह 100त्न बांस के गूदे से बने टॉवलस, बेहतर जल अवशोषण और जल्दी सूखने वाली विशेषताओं के साथ एक रेशनी - मुलायम स्पर्श प्रदान करते हैं । द प्लश टेरी टॉवल रेंज में कॉटन और बांस के मिश्रण है, जो स्नान के लिए, हाथ के लिए, दोपहर के भोजन के लिए, चेहरे और जूनिया टॉवल सहित विभिन्न प्रकार के टॉवल में उपलब्ध हैं। स्ट्रैप्ड और चेक्ड टॉवलस रेंज को पूरा करते हुए, रंग स्थिरता, कोमलता अर स्थायी गुणवत्ता के साथ दैनिक जरूरतों को पूरा करते हैं । रामराज कॉटन के प्रबंध निदेशक श्री अरुण ईश्वर ने कहा, मृथु टॉवल का लॉन्च हमारे ग्राहकों के लिए असाधारण गुणवत्ता, अभिनव डिज़ाइन और संधारणीय विकल्प प्रदान करने के लिए रामराज कॉटन के अटूट समर्पण का उदाहरण है। चाहे कोई प्रीमियम कम्फोर्ट, पर्यावरण के प्रति जागरूक सामग्री या व्यवहारिक कार्यक्षमता चाहता हो, कुछ न कुछ मृथु टॉवल संग्रह में मिलते हैं। यह परिचय भारतीय घरों में अद्वितीय लालित्य और उत्कृष्टता लाने की राजराज कॉटन की विरासत को पुष्ट करता है । ब्रांड के साथ अपने जुड़ाव पर बात करते हुए मीनाक्षी चौधरी ने कहा, मुझे रामराज कॉटन द्वारा मृथु टॉवल के लिए ब्रांड एंबेसडर के रूप में चुने जाने पर बहुत गर्व है, एक ऐसा ब्रांड जिसने लगातार भारत की समृद्ध परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को कायम रखा है । यह सहयोग मेरे मूल्यों के अनुरूप है, क्यों कि यह गुणवत्ता, प्रमाणिकता और संधारणीय प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर देता है । एसे ब्रांड का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्सु हूँ, जो न केवल असाधारण उत्पाद प्रदान करता है बल्कि भारतीय शिल्प कौशल और नवाचार के सार का भी जश्न मनाता है ।

अगले 5 सालों में मध्य प्रदेश में बनेंगी 1 लाख किलोमीटर सड़कें, विकास को मिलेगी रफ्तार

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने अगले पांच साल में 1 लाख किलोमीटर सड़कें बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जिससे राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। 2025 के तहत यह योजना ग्रामीण सड़कों, स्टेट हाईवे, और नेशनल हाईवे के विस्तार पर केंद्रित है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे नेटवर्क दो साल में अमेरिका से बेहतर होगा। इस आर्टिकल में हम 2025 की योजना, इसके लाभ, और कार्यान्वयन की जानकारी साझा करेंगे। मध्य प्रदेश में 2025 की यह मेगा योजना केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन नीति का हिस्सा है। 10 नए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत 5,800 करोड़ रुपये की लागत से हुई, जो 328 किलोमीटर सड़कें जोड़ेगी। इसके अलावा, 12,000 करोड़ रुपये के 6 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है, जो 400 किलोमीटर कवर करेंगे। अगले पांच साल में 1 लाख किलोमीटर सड़कों में ग्रामीण सड़कें, स्टेट हाईवे, और

औद्योगिक कॉरिडोर शामिल हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 बजट में 3,500 किलोमीटर सड़कों और 70 पुलों का प्रस्ताव है।

प्रमुख विशेषताएं और लाभ

कनेक्टिविटी: हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार तक पहुंच आसान होगी।

आर्थिक विकास: सड़कें औद्योगिक क्लस्टर और 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों (14,500 एकड़) को जोड़ेंगी, जिससे 3 लाख नौकरियां पैदा होंगी।

कृषि लाभ: किसानों को अपनी उपज मंडियों तक ले जाने में आसानी होगी, जिससे उनकी आय बढ़ेगी।

पर्यटन: बेहतर सड़कें खजुराहो, सांची, और ओरछा जैसे पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देंगी।

अभी क्या हैं चुनौतियां और उनका समाधान

2025 में भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी, और फंडिंग जैसी चुनौतियां हैं। याद दिला दें कि सरकार PPP मॉडल और केंद्रीय सड़क निधि का उपयोग कर रही है। गडकरी ने कहा सड़कें केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि खुशहाली की लाइफलाइन हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने हर जिले में सड़क निर्माण की प्रगति की निगरानी के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई है।

क्या है भविष्य की योजनाएं?

मध्य प्रदेश का विजन 'विकसित मध्य प्रदेश 2047' 250 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखता है। आपको बता दें कि 2025-26 में 3 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे। इसमें भोपाल-विदिशा रोड पर सुखी सेवनिया फ्लाईओवर (48 करोड़ रुपये) और 500 रेलवे ओवरब्रिज/फ्लाईओवर शामिल हैं।

मध्य प्रदेश की नई रफ्तार

2025 मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। 1 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण ग्रामीण-शहरी कनेक्टिविटी, रोजगार, और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा। नितिन गडकरी और सीएम मोहन यादव की अगुआई में यह योजना मध्य प्रदेश को भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनाएगी।

आम खाने वालों के लिए खुशखबर, मध्य प्रदेश के इन शहरों में आम के दाम में आई भारी गिरावट

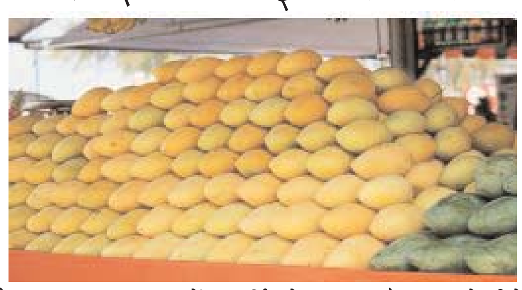

नई दिल्ली, एजेंसी। मध्य प्रदेश में गर्मियों का मौसम आते ही फलों का राजा आम बाजारों में छा जाता है। इस साल 2025 में, मध्य प्रदेश के बाजारों में आम की आवक में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण इसके दाम में काफी कमी आई है। यह खबर आम प्रेमियों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। इंदौर, भोपाल, और जबलपुर जैसे प्रमुख शहरों में आम अब किफायती दामों पर उपलब्ध है। आइए जानते हैं इस गिरावट के कारण, बाजार की स्थिति और उपभोक्ताओं के लिए इसका क्या मतलब है। मध्य प्रदेश के प्रमुख मंडियों जैसे इंदौर की चोइथराम मंडी और भोपाल की करोंद मंडी में आम की दैनिक आवक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जहां पिछले साल अप्रैल में 15-20 ट्रक आम रोजाना आते थे, वहीं इस साल यह संख्या 30-35 ट्रकों तक पहुंच गई है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से आने वाली किस्में जैसे बंगनपल्ली, केसर, और दशहरी बाजारों में छाई हुई हैं।

इस बढ़ी हुई आपूर्ति के कारण आम के दाम 100-150 रुपये प्रति किलो से घटकर 60-80 रुपये प्रति किलो हो गए हैं। इस साल मध्य प्रदेश में मौसम ने भी आम की पैदावार को बढ़ावा दिया है। समय पर हुई बारिश और अनुकूल तापमान ने फूलों के बनने और फल पकने की प्रक्रिया को बेहतर बनाया। इसके अलावा, कीटों और फल मक्खियों का प्रकोप भी पिछले सालों की तरह कम रहा है। किसानों का कहना है कि इस साल की फसल की गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही शानदार हैं, जिसने बाजार में आपूर्ति को बढ़ाया और दाम को नीचे लाया। उपभोक्ता बेहद खुश हैं। भोपाल की गृहिणी राधिका शर्मा कहती हैं, पिछले साल आम इतने महंगे थे कि हम ज्यादा नहीं खरीद पाए। इस बार 70 रुपये किलो में अच्छी क्वालिटी के आम मिल रहे हैं, जो पूरे परिवार के लिए खुशी की बात है। वहीं, व्यापारियों का कहना है कि बढ़ी हुई आवक के कारण उनकी बिक्री में भी इजाफा हुआ है। इंदौर के व्यापारी मनोज गुप्ता बताते हैं, अधिक आपूर्ति से हम ज्यादा आम बेच पा रहे हैं, जिससे ग्राहकों की संख्या बढ़ी है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ हफ्तों में आम की आपूर्ति और बढ़ सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से दशहरी और लंगड़ा जैसी किस्में भी मध्य प्रदेश के बाजारों में आने लगेंगी। इससे मध्यप्रदेश मेगो प्राईज ड्राप और ज्यादा होने की संभावना है। हालांकि, व्यापारियों को सलाह दी जा रही है कि वे फल की गुणवत्ता बनाए रखें ताकि उपभोक्ताओं का भरोसा बना रहे। यह खबर मध्य प्रदेश के आम प्रेमियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। बढ़ी हुई आवक, अनुकूल मौसम, और बेहतर फसल ने आम को हर घर की पहुंच में ला दिया है।

मप्र के इस जिलें में मिला विशाल सोने का भंडार खदानों में उतरीं मशीनें, प्रदेश होगा मालामाल

नई दिल्ली, एजेंसी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में 2025 के तहत दो नए जगहों पर सोने के बड़े भंडार मिले हैं, जिससे राज्य की आर्थिक तरक्की को नया रास्ता मिला है। चितरंगी ब्लॉक के अमिलहवा और सोनपुरवा गांवों में सोने की खदानें खोजी गई हैं, जहां गरिमा नेचुरल रिसोर्सेज ने खनन के लिए मशीनें उतार दी हैं। यह खोज सिंगरौली को कोयला खनन के साथ-साथ सोने के केंद्र के रूप में स्थापित करेगी।

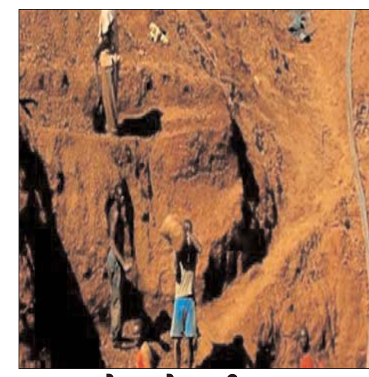

सोने की खोज और खनन की शुरुआत

सिंगरौली में दो नए गोल्ड ब्लॉक खोजे गए हैं, जहां हर टन अयस्क से करीब 1.5 ग्राम सोना मिलने की उम्मीद है। चितरंगी ब्लॉक के अमिलहवा और सोनपुरवा में खनन का काम शुरू हो गया है, और इन खदानों का संचालन गरिमा नेचुरल रिसोर्सेज को सौंपा गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने खनन से होने वाली आय को बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन में निवेश करने की योजना बनाई है। यह खोज सिंगरौली की चार खदानों को और मजबूत करेगी।

खनन में आने वाली चुनौतियां और समाधान

खनन में पर्यावरणीय प्रभाव और स्थानीय समुदायों का विस्थापन चुनौतियां हैं। सरकार ने पर्यावरण मंजूरी और पुनर्वास योजनाओं को प्राथमिकता दी है। सिंगरौली में खनन के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने ग्रामीणों के लिए रोजगार और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं।

भविष्य की संभावनाएं: 2025 मध्य प्रदेश को भारत का नया सोना खनन हब बना सकता है। सिंगरौली की खदानों से देश का सोना उत्पादन 1.6 मीट्रिक टन तक बढ़ने की उम्मीद है। सरकार ने नए ब्लॉकों की खोज के लिए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की रफ्तार बढ़ा दी है।

आर्थिक प्रभाव और लाभ

रोजगार सृजन: खनन से सिंगरौली में हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी।

आर्थिक समृद्धि: सोने की खदानों से मध्य प्रदेश की त्रष्ठक्क में वृद्धि होगी। भारत का सोना आयात बिल कम करने में यह खोज महत्वपूर्ण होगी।

निवेश: निजी कंपनियां और विदेशी निवेशक सिंगरौली में रुचि दिखा रहे हैं।

पर्यटन: सोने की खदानों के कारण सिंगरौली पर्यटन मानचित्र पर उभरेगा।

एक्सिस बैंक के वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही और वार्षिक परिणाम

मुंबई, एजेंसी। भारत में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकों में से एक एक्सिस बैंक ने आज अपने वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही और वार्षिक परिणामों की घोषणा की, जिसमें 26,373 करोड़ रुपये का वार्षिक शुद्ध लाभ दर्ज किया गया, जो वित्त वर्ष 24 में 24,861 करोड़ रुपये के लाभ की तुलना में पिछले वर्ष की तुलना में 6 प्रतिशत अधिक है। बैंक की शुद्ध ब्याज आय 6 प्रतिशत बढ़कर 13,811 करोड़ रुपये हो गई। वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही के लिए शुद्ध ब्याज मार्जिन 3.97 प्रतिशत रहा और तिमाही दर तिमाही 4 बीपीएस बढ़ा। सीएएसए में तिमाही दर तिमाही के आधार पर 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई और सीएएसए अनुपात 38 प्रतिशत क्यूएबी पर रहा। 31 मार्च 2025 तक, बैंक के रिपोर्ट किए गए सकल एनपीए और शुद्ध एनपीए का स्तर क्रमशः 1.28 प्रतिशत और 0.33 प्रतिशत था, जबकि 31 मार्च 2024 को यह 1.43 प्रतिशत और 0.31 प्रतिशत था। बैंक की शुल्क आय वित्त वर्ष 25 में 12 प्रतिशत साल दर साल और 16 प्रतिशत तिमाही दर तिमाही बढ़कर 6,338 रुपये हो गई। खुदरा शुल्क में 14 प्रतिशत साल दर साल और 22 प्रतिशत तिमाही दर तिमाही की वृद्धि हुई; और बैंक की कुल शुल्क आय का 75 प्रतिशत हिस्सा रहा। बैंक का समग्र पूंजी पर्याप्तता अनुपात 14.67 प्रतिशत के सीइटी 1 अनुपात के साथ 17.07 प्रतिशत रहा। बैंक की घरेलू सहायक कंपनियों ने स्थिर प्रदर्शन किया, और वित्त वर्ष 2025 में उनका शुद्ध लाभ 1,768 करोड़ रुपये रहा, जो साल-दर-साल 11 प्रतिशत की वृद्धि है। तिमाही के दौरान बैंक ने 170 शाखाएँ जोड़ीं, जिससे इसका समग्र वितरण नेटवर्क 31 मार्च 2025 तक 5,876 घरेलू शाखाओं और विस्तार काउंटरों तक पहुँच गया, साथ ही 3,194 केंद्रों में 234 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग आउटलेट (बीसीबीओ) भी स्थापित हो गए।

टेक्नो स्पोर्ट ने उत्तर भारत में पहला स्टोर खोला

इंदौर एजेंसी। टेक्नो स्पोर्ट, जो प्रदर्शन-आधारित एक्टिवियर में एक प्रमुख नाम है, ने उत्तर भारत में अपनी पहली विशेष ब्रांड स्टोर (ईबीओ) खोलने की घोषणा की है। इंदौर में स्टोर 24 अप्रैल 2025 को फीनिक्स सिटाडेल मॉल में खोला गया है। जो मध्य भारत के दिल में ब्रांड के प्रदर्शन, नवाचार और शैली का एक अनूठापन है। **नया स्टोर और पेशकशें:** यह स्टोर 1200 वर्ग फुट में फैला हुआ है और इंदौर में सक्रिय जीवनशैली के शौकीनों के लिए एक आकर्षक खरीदारी अनुभव प्रदान करता है। स्टोर में टेक्नो स्पोर्ट के सबसे अधिक बिकने वाले उत्पादों के साथ-साथ स्थानीय पसंद के अनुसार तैयार किए गए नए ट्रेंडिंग उत्पादों श्रृंखला है। ये उत्पाद ऊर्जावान और शैली-जागरूक उपभोक्ताओं के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो आराम और प्रदर्शन दोनों को महत्व देते हैं। ग्राहक कॉटफ्लेक्स संग्रह का पता लगा सकते हैं, जो वसंत-ग्रीष्म ऋतु की मांगों के लिए इंजीनियर किए गए एक्टिवियर की एक श्रृंखला है। इस संग्रह की प्रमुख विशेषताओं में एंटी-माइक्रोबियल तकनीक शामिल है जो स्वच्छता और ताजगी सुनिश्चित करती है। टेक्नो स्पोर्ट के एक्टिवियर संग्रह में यूवीएफ 50+ फैब्रिक है जो त्वचा को यूवी किरणों और सूर्य की क्षति से बचाता है।

देश में सबसे महत्वपूर्ण जिले के कलेक्टर,चर्चा में है नाम!

नई दिल्ली, एजेंसी। यूपीएससी में आईएएस के रूप में हर साल कई प्रशासनिक अधिकारियों को चुना जाता है। लेकिन, कुछ साल की सेवा के बाद कुछ ही ऐसे अफसर होते हैं, जो समाज में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब होते हैं। जहां तक प्रशासनिक कामकाज और सख्ती का सवाल है, तो वो इस पद की अपनी कार्यशैली है। लेकिन, अलग छाप उसी अफसर की बनती है, जो अपने नए प्रयोगों से समाज को कोई नई दिशा देता है या समाज जिसे अपना समझता है। ऐसे चंद अधिकारियों में सत्येंद्र कुमार झा को भी गिना जाता है, जो हाल ही में वाराणसी के नए कलेक्टर बनाए गए। यूपीएससी परीक्षा में सत्येन्द्र कुमार को 71वीं रैंक हासिल हुई थी। अब उनका नाम इसलिए चर्चा में आया कि वे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के कलेक्टर बनाए गए हैं।

2013 बैच के आईएएस अधिकारी सत्येन्द्र कुमार को उनके कुशल प्रशासनिक कौशल और जनसेवा के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है। अभी तक वे जिस जिले में कलेक्टर या जिस भी विभाग में प्रभारी रहे, उन्होंने वहां नए प्रयोग किए जिनके अच्छे नतीजे सामने आए। सत्येन्द्र कुमार ने अपने 12 साल के करियर में कई चुनौती वाले पदों पर अपनी योग्यता साबित की। उन्होंने देवरिया और जौनपुर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने प्रशासनिक दक्षता और जनसंपर्क में अपनी छाप छोड़ी। इसके बाद, बरेली में मुख्य विकास अधिकारी के रूप में उन्होंने विकास कार्यों को गति दी। लखनऊ में विशेष सचिव (बेसिक शिक्षा विभाग) के पद पर रहते हुए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार किए।

ढ्ढस् बनने से पहले वे भारतीय राजस्व सेवा में चयनित हुए थे। बतौर आईआरएस वे कोलकाता में असिस्टेंट कमिश्नर कस्टम एंड एक्साइज और

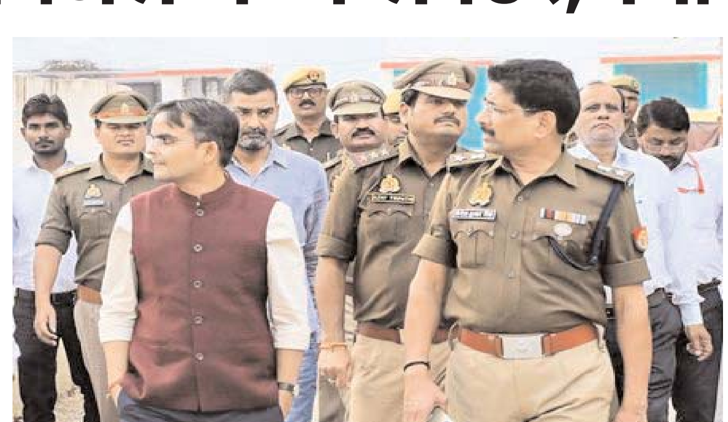

सर्विस टैक्स के पद पर तैनात थे। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बीई की डिग्री हासिल की और 2013 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में कदम रखा। उन्होंने महोबा, महाराजगंज और बाराबंकी में कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दीं, जहां उनके कार्यों की सराहना हुई। खास तौर पर महोबा और महाराजगंज में उन्होंने स्थानीय समस्याओं को हल करने और विकास परियोजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण काम किया। वे उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री के विशेष सचिव के रूप में कार्यरत रहे, जहां उन्होंने नीति निर्माण और प्रशासनिक समन्वय में अहम भूमिका निभाई।

सत्येन्द्र कुमार का जन्म 30 अप्रैल 1987 को बिहार के मधुबनी जिले में हुआ। इनके माता जी का नाम कमला रानी झा और पिता जी का नाम राधा रमण झा है। इनकी शुरुआती पढ़ाई पैतृक गांव के ही सरकारी प्राथमिक विद्यालय में हुई। यही कारण है कि ये समय मिलते ही अक्सर छोटे-छोटे बच्चों को खुद पढ़ाने सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पहुंच जाते हैं। जब वे बरेली में सीडीओ के पद पर थे, तब प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए उन्होंने अनूठी पहल शुरू की थी। बच्चों को पढ़ाने के लिए लोगों से भी अपील की कि वे बच्चों को पढ़ाने आएं। वे खुद भी सप्ताह में तीन बार प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाते थे। सीडीओ की इस मुहीम से बाद में करीब 40 लोग जुड़ गए थे। यह प्रयोग उन्होंने इसलिए किया कि स्कूल में तैनात शिक्षक छुट्टी पर थे और बच्चों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही पढ़ा रहा था। इस स्कूल में 34 बच्चों का एडमिशन था, जबकि पढ़ने के लिए उस दिन सिर्फ 9 बच्चे ही थे। सत्येंद्र कुमार ने जब बच्चों से नाम लिखवाया, तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में महज एक बच्चा ही अपना नाम लिख पाया। जिस पर सीडीओ ने खुद ही बच्चों पढ़ाने की ठानी और स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। सीडीओ की पढ़ाई का असर भी दिखने लगा है पहले जो बच्चे अपना नाम नहीं लिख पाते थे, वे बच्चे हिंदी और अंग्रेजी में अपना नाम लिखने लगे है। सीडीओ सप्ताह में तीन बार कार्यालय जाने से पहले बच्चों को पढ़ाने पहुंचते थे।

एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव-2025

डिजिटल स्टेट बनने की ओर अग्रसर मध्यप्रदेश

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में बढ़ते विश्वास के साथ आईटी क्षेत्र में निवेश के सकारात्मक रूझान और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए लागू की गई नई नीतियों से मध्यप्रदेश अब देश का डिजिटल स्टेट बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। पिछले एक वर्ष में हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव , देश के विभिन्न महानगरों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यूके, जर्मनी और जापान में रोड-शो के जरिये उद्योगपतियों और निवेशकों को मध्यप्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया। इसी के साथ गत फरवरी माह में भोपाल में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) के सफल परिणामों ने मध्यप्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। इसमें सबसे प्रमुख रहा आईटी सेक्टर, जो प्रदेश को आईटी क्षेत्र में एक नई पहचान देने का माध्यम बना। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की इसी पहल के तहत रविवार को इंदौर के ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में प्रदेश के पहले एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव-25 का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश-दुनिया के टेक दिग्गज शामिल होंगे।

मध्यप्रदेश डिजिटल नवाचार की दिशा में आगे बढ़ते हुए राज्य के 02 शहरों को सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल पर विकसित करने जा रहा है। इस पायलेट प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। राज्य में अभी एग्रीटेक, स्कूल एजुकेशन, वन, बिजली और पुलिस महकमें में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है।

ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैनुफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड),12 हजार करोड़ के निवेश और 5 हजार नौकरियों के साथ जल्द आकार लेगा। यह टीएमजेड देश में अपनी तरह का पहला जोन होगा। इसमें सिम, चिप, एंटीना और अन्य उपकरण निर्मित होंगे। यहाँ सभी एसेसरीज सिस्टम्स, कम्पोनेंटस, वाइ-फाई, ऑप्टिकल्स, मोबाइल डिवाइसेज, सिमकार्ड, एंटीना, टेलीकॉम चिप्स सहित टेलीकॉम सेक्टर में नई 6जी टेक्नॉलाजी के लिए अनुसंधान एवं विकास के कार्य भी किए जाएंगे। टेलीकॉम सेक्टर की डिक्सॉन, वॉयकॉन, आईबीएम, निक्सन एवं एरिक्सन जैसी सभी बड़ी कम्पनियां यहां निवेश करने के लिए आएंगी।

ग्वालियर आईटी पार्क में लगभग 70 एकड़ एवं साडा ग्वालियर क्षेत्र में 300 एकड़ भूमि की मांग निवेशकों द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर साडा ग्वालियर की 271 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय हो चुका है। नवीन आईटी नीतियां मध्यप्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बेहद अनुकूल हैं। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में उभरते सभी अवसरों का लाभ उठाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ईएमसी) 2.0 देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक अग्रणी पहल है। यह योजना एक गेम चेंजर है और निश्चित रूप से इस क्षेत्र को अगले स्तर पर ले जाएगी। ईएमसी 2.0 योजना में भोपाल के बैरसिया रोड पर बांदीखेड़ी में और जबलपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर डेवलप होगा ।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जीआईएस - भोपाल में प्रदेश में बेहतर निवेश के लिए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। इस तारतम्य में लिए गए निर्णयों का नतीजा है नीति क्रियान्वयन और आधारभूत संरचना विकास। विभागीय सक्रियता ने राज्य को आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम क्षेत्रों में एक संभावित निवेश स्थल से वास्तविक और समृद्ध निवेश-स्थल में परिवर्तित कर दिया है।

जीआईएस- भोपाल में लगभग 100 आईटी कंपनियों के लगभग 34 हजार करोड़ राशि के निवेश प्रस्ताव से दो लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इनमें से 28 प्रोजेक्ट दो माह में मूर्तरूप ले रहे हैं। राज्य के दो उभरते तकनीकी केंद्र इंदौर और भोपाल इन क्षेत्रों में निवेश के लिये आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग (केपीओ), बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) और डाटा सेंटर की स्थापना के लिए निवेशकों को आकर्षित किया है।

राज्य में डाटा सेंटर के क्षेत्र में कंपनियां आ रहीं हैं , जिससे निवेश का आकार लगातार बढ़ रहा है। सेन्ट्रल ऑफ एक्सीलेंस, इन्क्यूबेशन सेन्टर और आईटी स्टार्ट-अप का मध्यप्रदेश में बेहतर ईको सिस्टम विकसित हो रहा है।

एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव - 2025 में स्टेक होल्डर डिजिटल एक्सपर्टस एवं निवेशकों को प्रदेश के तकनीकी और डिजिटल नवाचार और उससे संबंधित आर्थिक दृष्टिकोण बारे में बताया जायेगा। इस अवसर पर नीतिगत घोषणाएं , ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, सेमीकंडक्टर्स, कॉमिक्स और एक्सटेन्डेड रियलिटी और ड्रोन्स से संबंधित गाइडलाइन्स जारी की जाएंगी। राज्य की जीसीसी, आईटी, आईटीईस, सेमीकंडक्टर्स, ड्रोन्स और एवीजीस-एक्सआर पॉलिसी मध्यप्रदेश को देश के डिजिटल स्टेट के रूप में उभारने में बेहद कारगर होंगी। एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव-2025, जहाँ डिजिटल भारत की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाएगा वहीं प्रदेश देश का डिजिटल स्टेट बनकर उभरेगा।

डिजिटल इंडस्ट्री के क्षेत्र में कार्य कर रहे उद्योगपतियों के साथ समन्वय, स्टार्ट-अप में उद्यमिता की संस्कृति को विकसित करने, प्राकृतिक गैस पर टैक्स कम करने और प्रदेश में स्टार्ट-अप कम्युनिटी को बढ़ावा देने का काम कर रही है। वॉक-टू-वर्क सुविधा के साथ आईटी पार्क विकसित करने, प्रदेश में डिजिटल इकोनॉमी मिशन प्रारंभ करने के साथ ही एआई -आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गतिविधियों की अन्य उद्योगों में स्वीकार्यता बढ़ाने की दिशा में भी राज्य सरकार कार्य कर रही है। एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव डिजिटल इंडस्ट्री के क्षेत्र में कार्य कर रहे उद्योगपतियों के बीच मजबूत रिश्तों का आधार बनेगी और सबके सहयोग से मध्यप्रदेश आईटी सेक्टर में अपनी विशेष पहचान स्थापित करेगा।

मोहन यादव की नवाचार के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत

डॉ. हितेष वाजपेयी
प्रवक्ता भाजपा मध्यप्रदेश

डॉ मोहन यादव सरकार टेक्नोलॉजी और डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश को वैश्विक टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव-2025 का शुभारंभ इंदौर के ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश की तकनीकी प्रगति को नई दिशा देने वाली चार महत्वपूर्ण नीतिगत दिशानिर्देशों का विमोचन करेंगे।

ये हैं प्रगति को दिशा देने वाले चार निर्देश

1. ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) नीति।
2. ड्रोन प्रोत्साहन एवं उपयोग नीति।
3. सेमीकंडक्टर नीति।
4. एवीजीसी-एक्सआर (एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स व एक्सटेंडेड रियलिटी) नीति।

इन नीतियों का लक्ष्य प्रदेश में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, नवाचार, स्टार्टअप्स और निवेश को प्रोत्साहित करना है, ताकि मध्यप्रदेश राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त डिजिटल और टेक्नोलॉजी गंतव्य के रूप में उभर सके। एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 प्रदेश के युवाओं, उद्यमियों, निवेशकों और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा और मध्यप्रदेश को डिजिटल इंडिया के सपनों के साथ जोड़ने में एक मील का पत्थर साबित होगा। आइए समझते हैं कि डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में इस सन्दर्भ में किस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने तकनीकी क्षेत्र में निवेश और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए चार प्रमुख नीतियाँ लागू की हैं।

1. ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) नीति 2025

उद्देश्यः राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग के केंद्र के रूप में स्थापित करना।

प्रमुख विशेषताएं

50 से अधिक जीसीसीएस को आकर्षित करने और 37,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने का लक्ष्य। इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे

टियर-2 शहरों को वैश्विक व्यापार हब के रूप में विकसित करना। 40 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी (अधिकतम 30 करोड़), किराया सहायता, और पेरोल सब्सिडी जैसे प्रोत्साहन। नोटकोरा आरएंडडी, अपस्किलिंग और पेटेंट फाइलिंग के लिए समर्थन। नो क्वेरी पोर्टल के माध्यम से सिंगल-विंडो।

2. ड्रोन नीति 2025

उद्देश्यः मध्य प्रदेश को ड्रोन निर्माण और तकनीक का प्रमुख केंद्र बनाना।

प्रमुख विशेषताएं

40 प्रतिशत पूंजीगत निवेश सब्सिडी (अधिकतम 30 करोड़)। तीन वर्षों के लिए 25 प्रतिशत किराया सहायता (अधिकतम 5 लाख प्रति वर्ष)। चिह्नित क्षेत्रों में आरएंडडी अनुदान 2 करोड़ तक। आईआईएसईआर भोपाल में प्रशिक्षण, निर्माण, और अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना। कृषि, आपदा प्रबंधन, सार्वजनिक सुरक्षा, और बुनियादी ढांचे में ड्रोन तकनीक का उपयोग।

3. सेमीकंडक्टर नीति 2025

उद्देश्यः राज्य को सेमीकंडक्टर डिजाइन और निर्माण का केंद्र बनाना।

प्रमुख विशेषताएं

40 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान (अधिकतम 150 करोड़)। 5 वर्षों के लिए 6 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी (अधिकतम 10 करोड़)। 10 वर्षों के लिए 2 प्रति यूनिट की रियायती बिजली दर। रियायती दरों पर भूमि उपलब्धता। 4 अरब से अधिक के परियोजनाओं के लिए कस्टमाइज्ड प्रोत्साहन पैकेज प्रोत्साहन।

4. एवीजीसी-एक्सआर नीति 2025

उद्देश्यः राज्य को एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी (एवीजीसी-एक्सआर) के क्षेत्र में अग्रणी बनाना।

प्रमुख विशेषताएं

- 25प्रतिशत पूंजीगत व्यय सब्सिडी (अधिकतम 30 करोड़)।
- तीन वर्षों के लिए 25 प्रतिशत किराया सहायता (अधिकतम 10 लाख प्रति वर्ष)।
- प्रति कर्मचारी 3,000 प्रति माह की रोजगार सृजन सहायता (एक वर्ष के लिए)।
- पंजीकरण लागत का 50 प्रतिशत सब्सिडी (अधिकतम 20 लाख)।
- तीन वर्षों के लिए बैंडविड्थ लागत की प्रतिपूर्ति (अधिकतम 50,000 प्रति वर्ष)।
- एआर, वीआर, और एआई जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना।
- अंतरराष्ट्रीय सह-उत्पादन और साझेदारियों के लिए 30 प्रतिशत व्यय की प्रतिपूर्ति (अधिकतम 2 करोड़)।
- महिला उद्यमिता और छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के लिए विशेष समर्थ।

इन नीतियों के माध्यम से, डॉ मोहन यादव की मध्य प्रदेश सरकार तकनीकी नवाचार, निवेश, और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे राज्य को एक प्रमुख तकनीकी हब के रूप में स्थापित किया जा सके।

परासिया क्षेत्र में पूरी गति से चल रहा जुआ, सट्टा व शराब का अवैध कारोबार: वीर बहादुर

छिन्दवाड़ा। भाजपा की सरकार में माफियाराज खूब फलफूल रहा है। राज्य व केन्द्र की भाजपा सरकार में जिले से तीसरा इंजन जुड़ने के जुआ, सट्टा व शराब का अवैध कारोबार पूरी गति से चल पड़े हैं, यह बात कांग्रेस के नेता अनेक मंचों से, आंदोलनों में व ज्ञापन में व्यक्त कर चुकी है। परासिया विधानसभा क्षेत्र में खुलेआम अवैध कारोबार को भाजपा सरकार का संरक्षण प्राप्त है यह बात पूरी तरह से सत्य व प्रमाणजनक है, इसकी पुष्टि स्वयं भाजपा के मंडल अध्यक्ष के द्वारा कर दी गई है। उक्त उदगार माध्यम से परासिया शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री वीर बहादुर सिंह ने व्यक्त किए। श्री सिंह ने जारी प्रेस विज्ञप्ति के अंत में कहा कि पुलिस व आबकारी विभाग इन अवैध कारोबार पर त्वरित संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करें अन्यथा कांग्रेस बढ़ते अपराध व अवैध कारोबार के खिलाफ जनहित में आंदोलन करेगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पुलिस व प्रशासन की होगी।

पानी बचाने को लेकर नुक्कड़ नाटक का हुआ मंचन

छिंदवाड़ा। जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत प्रदेश के जिलों में विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जा रही है। इसी श्रृंखला में छिन्दवाड़ा कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह के निर्देशन एवं जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक श्री अखिलेश जैन व ब्लाक समन्वयक श्री भवानीप्रसाद कुमरे के मार्गदर्शन में विकासखंड-मोहखेड़ अंतर्गत लिंगा सेक्टर के ग्राम- खुनाझिर कलाँ में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक का मंचन ग्राम पंचायत प्रागंण में नवांकुर संस्था-प्रभात युवा विकास मंडल के द्वारा किया गया जिसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जल संरक्षण,स्वच्छता,ठोस कचरा प्रबंधन संदेश दिया गया। नुक्कड़ नाटक के पश्चात जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य श्री एस.व्ही.नासेरी,सीएमसीएलडीपी परामर्शदाता कैलाश सोनेवार,ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति से अशोक साहू,डॉ.पवन नेमा,स्कूल शिक्षक स्टाफ से अर्जुन पवार,सुनीता बोनिया,शिवानी सोनी, प्रियंका झरबड़े, कल्पना पवार, ग्रा.रो.सहा. सुनील नांदेकर, नागरिकगणों सहित स्कूली छात्र/छात्रा सम्मिलित रहे।

सांसद बंटी विवेक साहू ने मरीज को दिलाई आर्थिक मदद

छिन्दवाड़ा। सांसद बंटी विवेक साहू की पहल पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने एक मरीज को 30 हजार की सहायता राशि स्वीकृत की है। इस राशि से मरीज का अस्पताल में बेहतर ईलाज हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि गंभीर रूप से बीमार मरीज के परिजनों ने पिछले दिनों सांसद श्री साहू से मुलाकात करते हुये बीमारीं के लिए आर्थिक सहायता राशि दिलाने की गुहार लगाई थी। जिसे गंभीरता से लेते हुये सांसद श्री साहू ने मुख्यमुंत्री श्री यादव को पत्र प्रेशित कर मरीज को ईलाज के लिए आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराने का निवेदन किया था। जिसके आधार पर मुख्यमंत्री श्री यादव ने उनकी स्वेच्छानुदान मद से उमरेठ के वार्ड नं. 14 निवासी सुनील पिता नानाजी कुशवाह को 30 हजार की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। आर्थिक सहायता मिलने पर मरीज और उनके परिजनों ने मुख्यमंत्री और सांसद का आभार व्यक्त किया है।

भाजपा सरकार की कर वृद्धि के खिलाफ मैदान में उतरी कांग्रेस

नगर के दो वार्डों में पहुंचकर कांग्रेस पदाधिकारियों ने लिया जनसमर्थन

छिन्दवाड़ा। नगर की जनता को कर के बोझ से मुक्त कराने कांग्रेस का महा हस्ताक्षर अभियान लगातार जारी है। आमजन का समर्थन जुटाने लगातार वार्डों में पहुंच रहे कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ता के वक्ताओं ने आमजन से कहा कि कांग्रेस के पार्षद दल द्वारा लगातार कर वृद्धि का विरोध किया गया बावजूद इसके भाजपा ने अपनी हठधार्मिता दिखाते हुए जनता पर जलकर, सम्पत्ति कर व स्वच्छता कर सहित अन्य कर में बढ़ोत्तरी कर दी गई।

नगर के वार्ड क्रमांक 28 एवं 30 में पहुंचे शहर कांग्रेस व कांग्रेस पार्षद दल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने घरों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में पहुंचकर भाजपा के द्वारा बढ़ाए गए कर के खिलाफ समर्थन स्वरूप हस्ताक्षर कराए गए। कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने आमजन से कहा कि भाजपा के द्वारा लगाए गए कर का सीधा असर जनता की जेब पर पड़ रहा है। बढ़े हुए कर से जनता को मुक्त कराने के लिए कांग्रेस का सतत अभियान संचालित हो रहा है जिससे जुड़कर जनता लगातार अपना विरोध प्रगट कर रही है।

किसानों को नरवाई न जलाने के लिए भी किया गया प्रेरित

नरवाई प्रबंधन के लिए सब स्वायलर यंत्र द्वारा नरवाई प्रबंधन तकनीक का उपस्थित किसानों के समक्ष किया गया प्रदर्शन

छिन्दवाड़ा। जिले के विकासखंड चौरई के ग्राम हरनाखेड़ी में कृषक श्री प्रदीप चौरसिया के खेत में नरवाई प्रबंधन के लिये सब स्वायलर यंत्र द्वारा नरवाई प्रबंधन तकनीक का उपस्थित किसानों के समक्ष प्रदर्शन किया गया। उपस्थित किसानों को राजस्व अनुविभागीय अधिकारी श्री प्रभात मिश्रा द्वारा किसानों को नरवाई ना जलाने के लिये प्रेरित किया गया एवं उपस्थित कृषकों को नरवाई प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान तहसीलदार चांद द्वारा उपस्थित कृषकों को नरवाई ना जलाने की अपील की गई एवं उन्हें जानकारी दी गई कि यदि कृषक नरवाई जलाते हैं तो उनके ऊपर जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा एवं पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जाएगी । इस प्रदर्शन तकनीक के समय विकासखंड चौरई के राजस्व अनुविभागीय अधिकारी श्री प्रभात मिश्रा, तहसीलदार चांद सुश्री शोभना ठाकुर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री उमेश पाटिल, कृषि विस्तार अधिकारी श्री सनोद मर्सकोले, कृषक श्री प्रदीप चौरसिया सहित ग्राम के अन्य कृषक उपस्थित थे।

पशुपालन एवं डेयरी विभाग व प्रांतीय राजपत्रित पशु चिकित्सा संघ के संयुक्त तत्वावधान में विश्व पशु चिकित्सा दिवस के उपलक्ष्य में किया गया शिविर का आयोजन

शिविर में 600 पशुओं का किया गया उपचार एवं टीकाकरण

छिन्दवाड़ा। जिले के ग्राम मेघासिवनी के बाहुवली जीव रक्षा संस्थान में विश्व पशु चिकित्सा दिवस के उपलक्ष्य में शिविर का आयोजन कर 600 पशुओं का स्वास्थ्य जांच, उपचार एवं टीकाकरण कार्य किया गया। उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग डॉ.एच.जी.एस. पक्षवार द्वारा गायों को गुड़-चना खिलाकर एवं पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद उपस्थित गौवंश की सेवा में तत्पर कर्मचारियों का सम्मान माला एवं कैप लगाकर किया गया। साथ ही सभी पशु चिकित्सकों व आंमत्रित अतिथियों का स्वागत माला व कैप लगाकर किया गया। इस अवसर पर उप संचालक डॉ.पक्षवार मुख्य अतिथि के रुप में शामिल हुये। साथ ही जनपद सदस्य श्री बुनकर एवं गौशाला के श्री प्रशांत जैन, गौशाला प्रबंधक श्री अजय जैन सम्मानीय अतिथि के रुप में उपस्थित रहे।

उप संचालक डॉ.पक्षवार ने कहा कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस की थीम एक संयुक्त टीम के रुप में पशु चिकित्सा क्षेत्र में कार्य करना है। पशु चिकित्सा क्षेत्र में सभी पशु चिकित्सक अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने पशु चिकित्सकों को कहा कि आप सौभाग्यशाली है जो बेजुवान पशुओं की सेवा करने का अवसर आपको मिला है। उन्होंने सभी पशु चिकित्सकों से अपने सेवा के प्रति तत्पर रहने के लिये भी आव्हान किया ।

इस अवसर पर श्री प्रशांत जैन ने गौशाला के द्वारा किये जा रहे गौवंश की सेवा कार्यों पर प्रकाश डाला। जनपद सदस्य श्री बुनकर ने पशु चिकित्सकों के कार्य को सराहा । प्रांतीय राजपत्रित पशु चिकित्सा संघ जिला छिन्दवाड़ा की अध्यक्ष डॉ.उषा क्षत्रिय ने बताया कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है । इसकी शुरुवात सन 2000 से हुई, जिसका उदेश्य पशु चिकित्सकों के कार्यों का सम्मान एवं जागरुकता लाना है। पशुओं की सेवा करने पर हमें गर्व है।

डेयरी फार्म के प्रबंधक डॉ.सोनू कदम ने उप संचालक डॉ.पक्षवार द्वारा जिले में किये जा रहे कार्यों के बारे बताया और उनके मार्गदर्शन के लिये आभार व्यक्त किया । इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ.छत्रपाल टाण्डेकर ने कहा कि सभी क्षेत्रों में पशु चिकित्सक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जैसे बैंक, सुरक्षा, अनुसंधान, कृषि के क्षेत्र में भी पशु चिकित्सकों द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। कार्यक्रम का मंच संचालन डॉ.बलराम सलेवार द्वारा किया गया एवं आभार प्रदर्शन कोषाध्यक्ष डॉ.नेहा साहू द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिले से गौशाला नोडल अधिकारी डॉ.प्राची चड्डा एवं अन्य पशु चिकित्सक उपस्थित थे।

शासकीय कन्या हायर सेकंडरी स्कूल में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन

छिन्दवाड़ा। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा श्री सुशांत हुद्दार के निर्देशन में सचिव श्री राकेश सिंह एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी विजय खोब्रागड़े द्वारा आज शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल कैलाश नगर छिंदवाड़ा में सालसा के मासिक कार्ययोजना अनुसार विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में नालसा नशा पीड़ितों के लिए विधिक सहायता योजना 2015 के अंतर्गत नशा पीड़ितों के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति नशे के दुष्प्रभाव से पीड़ित है एवं नशे की आदत से मुक्त होना चाहता है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति को नशामुक्ति केंद्र में प्रवेश दिलाने एवं अन्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करने में सहायता कर सकता है साथ ही साइबर अपराध के विषय में भी जानकारी दी गई।

जल संरक्षण के अंतर्गत रंगोली व चित्रकला प्रतियोगिता संपन्न

छिन्दवाड़ा। मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत आज नगर पालिका जुन्नारदेव के द्वारा संचालित पंडित रविशंकर स?कूल में विद्यार्थियों के द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत रंगोली व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा भाग लिया गया और जल संरक्षण, जल ही जीवन है की थीम पर रंगोली, चित्रकला का प्रदर्शन किया गया तथा जल स्त्रोतों के आसपास एवं नदियों, तालाबों को सुरक्षित करने के लिए स्वच्छता पर शपथ ली गई और आने वाले समय में जल के अभाव को देखते हुए जल स्त्रोत को बचाना एवं जल का सही उपयोग करने के लिए शपथ ली गई। इस आयोजन में नगर पालिका अध्यक्ष श्री रमेश सालोडे, मुख्य नगरपालिका अधिकारी सुश्री नेहा धुर्वे व वार्ड पार्षद सहित स्कूल के सभी स्टाफ की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ

पानी बचाने को लेकर नुक्कड़ नाटक का मंचन

छिन्दवाड़ा। राज्य शासन के दिशा-निर्देशानुसार जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत प्रदेश के जिलों में विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जा रही है। इसी श्रृंखला में कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह के निर्देशन एवं म.प्र.जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक अखिलेश जैन व ब्लॉक समन्वयक श्री भवानीप्रसाद कुमरे के मार्गदर्शन में विकासखंड मोहखेड़ के अंतर्गत लिंगा सेक्टर के ग्राम खुनाझिरकला में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक का मंचन ग्राम पंचायत प्रागंण में नवांकुर संस्था-प्रभात युवा विकास मंडल के द्वारा किया गया।

UDYOG EVAM ROJGAR VARSH 2025
INVEST MADHYA PRADESH
मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
MPS@DC INFOTECH ENGINE OF M.P.

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

देश का टेक्नोलॉजी हब बनने की ओर अग्रसर मध्यप्रदेश

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

मध्यप्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 के संकल्पों को साकार करता मध्यप्रदेश

शुभारंभ

डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश द्वारा

27 अप्रैल 2025 I सायं 5:00 बजे

ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर, इंदौर

अवसरों का प्रदेश मध्यप्रदेश...

इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां

- ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पॉलिसी 2025
- ड्रोन प्रमोशन एवं यूसेज पॉलिसी 2025
- आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2023
- एवीजीसी-एक्सआर पॉलिसी 2025
- सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025

टेक ईकोसिस्टम

15+ आईटी पार्क | **5** आईटी सेज़ | **2000+** आईटी, आईटीईएस यूनिट | **50+** बड़ी आईटी कंपनियां

1200+ टेक स्टार्ट-अप्स | **200K+** रोज़गार के अवसर | **2** टेक यूनिकॉर्न

D-11017/25

आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2025

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

फोकस क्षेत्र

- आईटी-आईटीईएस
- एवीजीसी-एक्सआर
- ड्रोन प्रौद्योगिकी
- ईएसडीएम और सेमीकंडक्टर
- डाटा सेंटर
- ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स

ipcell-mp@mpsedc.com I Website : mpsedc.mp.gov.in I #MPTechGrowthConclave2025 I #TechDestinationMP

सीधा प्रसारण Webcast.gov.in/mp/cmevents @Cmmadhyapradesh @jansampark.madhyapradesh @Cmmadhyapradesh @jansamparkMP JansamparkMP